सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 185, नई दिल्ली, शुक्रवार 12 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ऐतिहासिक जीत – प्रेरणा कुमारी और मधु सिंह दास...
06 ग्रामीण साक्षरता: जमीनी स्वयंसेवक साक्षरता को कैसे बढ़ा सकते हैं
08 वधिक डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए भेजी वैन को हरी झंडी दिखाई

भारत प्रवास अवॉर्ड्स 2025 में यात्री परिवहन क्षेत्र की उत्कृष्टता का सम्मान; नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) ने आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत प्रवास अवॉर्ड्स 2025 का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर सरकार, उद्योग और मोबिलिटी इकोसिस्टम की कई दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेडबस के सीईओ प्रकाश संगम, टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (आईएटीए-IATA) के प्रेसिडेंट सतीश सेहरावत और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी-AIMTC) के प्रेसिडेंट डॉ. हरीश सभरवाल भी उपस्थित रहे।

BOCI के वरिष्ठ नेतृत्व में चेयरमैन जगदेव सिंह खालसा, प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन, नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट मोहम्मद अफ़ज़ल, जनरल सेक्रेटरी डी.आर. धर्मराज, ट्रेज़रर हर्ष कोटक और एमएम एक्टिव साइ-टेक कम्युनिकेशन्स के एग्ज़िक्यूटिव चेयरमैन एवं कार्यक्रम क्यूरेटर जगदीश पाटणकर शामिल रहे।

भारत प्रवास अवॉर्ड्स, जिसका आयोजन पहले द्विवार्षिक प्रवास कार्यक्रम के साथ किया जाता था, अब हर साल आयोजित होंगे। इन अवॉर्ड्स का उद्देश्य यात्री परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है। यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विज़न से जुड़ी है और उन योगदानकर्ताओं को पहचान देती है, जो आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

इस साल रेडबस लीड पार्टनर के रूप में जुड़ा। देशभर से 230 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से 63 विजेताओं को सम्मानित किया गया। सबसे खास आकर्षण रहा पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड्स, जिसे रेडबस ने बस ऑपरेटरों के अहम योगदान को मान्यता देने के लिए

शुरू किया। इस श्रेणी के अंतर्गत राइजिंग स्टार अवॉर्ड्स (तेजी से बढ़ रहे और इनोवेशन लाने वाले ऑपरेटरों के लिए) और STU अवॉर्ड्स (स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए) दिए गए। जनता की भागीदारी और डेटा-आधारित मूल्यांकन से चुने गए ये अवॉर्ड्स और भी खास बन गए। इसके अलावा प्रवास एक्सीलेंस अवॉर्ड्स के तहत 44 विजेताओं को संचालन, सेवा, टेक्नोलॉजी अपनाने और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

इस मौके पर BOCI ने प्रवास 5.0 की भी घोषणा की। यह देश का प्रमुख मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट शो है, जिसका आयोजन अगस्त 2026 में गांधीनगर (गुजरात) के हेलिपैड एग्ज़िबिशन सेंटर में होगा। इस अवसर पर एक विशेष प्रीव्यू फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को प्रवास 5.0 के पैमाने, दृष्टिकोण और मुख्य आकर्षणों की झलक दिखाई गई।

कार्यक्रम की एक और बड़ी घोषणा रही 'स्टेट रैंकिंग इंडेक्स', जिसे BOCI वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। यह इंडेक्स बस संचालन की सुगमता और निवेश माहौल का आकलन करेगा। इसमें बिज़नेस एनवायरनमेंट, वर्कफोर्स, सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और संस्थागत बसों जैसे मानकों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों में सुधार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। इस इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट प्रवास 5.0 (2026) में जारी की जाएगी।

अवाड्र्स समारोह के बाद BOCI ने 'BOCI डायलॉग' नाम से आधे दिन का एक लीडरशिप फोरम आयोजित किया। इसमें पॉलिसी मेकर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स, वाहन निर्माता, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के दिग्गज एक साथ आए। इस मंच का उद्देश्य भारत की मोबिलिटी के भविष्य पर चर्चा करना था।

पहला सत्र 'विकसित भारत के लिए भविष्य-तैयार मोबिलिटी' पर केंद्रित था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह 2047 तक भारत के समान, कुशल और टिकाऊ विकास की रीढ़ बन सकता है। दूसरा सत्र 'स्मार्ट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए नीतिगत नवाचार' पर रहा, जिसमें चर्चा हुई कि कैसे प्रगतिशील नीतियाँ स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा दे सकती हैं, सुरक्षा को मज़बूत बना सकती हैं और एक पारदर्शी, भविष्य-तैयार परिवहन इकोसिस्टम का निर्माण कर सकती हैं।

भारत प्रवास अवॉर्ड्स 2025 और BOCI डायलॉग ने मिलकर यह संदेश दिया कि BOCI भारत के परिवहन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह आयोजन 'विकसित भारत 2047' की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसने न केवल उत्कृष्टता का सम्मान किया बल्कि यह भी दोहराया कि पॉलिसी मेकर्स, उद्योग जगत और इनोवेटर्स की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि भारत को सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन भविष्य की ओर ले जाया जाए।

साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की छवि और आवाज़ का दुरुपयोग करके बनाए गए डीपफेक प्रचार वीडियो एक अत्यंत परिष्कृत ठगी तंत्र का हिस्सा हैं, जिसमें एआई से छेड़छाड़, नकली मीडिया ब्रांडिंग और मनोवैज्ञानिक निशाना साधना शामिल है।

डीपफेक निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ उपाय

1. त्वरित पहचान और हटाना

1. एआई आधारित डीपफेक पहचान उपकरणों (जैसे Hive Moderation, Resemble.ai, Deepfake-O-Meter) का उपयोग करना चाहिए ताकि वायरल सामग्री को स्कैन कर बदली गई मीडिया को चिन्हित किया जा सके।

2. Meta, YouTube, X जैसे प्लेटफॉर्म्स से समन्वय कर चिन्हित वीडियो और नकली वेबसाइट्स को शीघ्र हटवाना चाहिए।

3. विज्ञापन नेटवर्क्स पर नजर रखना चाहिए जो नकली समर्थन के साथ पेड प्रमोशन चला रहे हैं।

2. जन-जागरूकता अभियान

1. टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी चेतावनी जारी करना चाहिए, जिससे नागरिकों को नकली निवेश योजनाओं से सावधान किया जा सके।

2. वित्त मंत्री के असली वीडियो क्लिप्स का उपयोग करना चाहिए जो इस धोखाधड़ी को खारिज करते हैं, ताकि विश्वसनीयता बने।

3. स्पष्ट ₹भरोसा न करें₹ संदेश और हेल्पलाइन नंबरों के साथ प्रिंट-रेडी पोस्टर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड तैयार करें।

3. डिजिटल स्वच्छता अभियान

1. "निवेश से पहले सत्यापन करें" संदेश को बढ़ावा दें:

2. योजनाओं की पुष्टि हमेशा सरकारी पोर्टल्स (जैसे PIB Fact Check) पर करें।

3. "गारंटीड डेली इनकम" या "एआई आधारित ऑटोमैटिक रिटर्न" जैसी योजनाओं पर कभी भरोसा न करें।

4. कानूनी और प्रवर्तन कार्रवाई

1. ऐसे सभी मामलों में IPC की धाराओं 419/420 और आईटी एक्ट की धाराओं 66D/67A के तहत एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जो छवि-प्रवंचना और धोखाधड़ी को कवर करती हैं।

2. UPI, क्रिप्टो वॉलेट्स और म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से धन के प्रवाह को ट्रैक करना चाहिए।

3. CERT-In और RBI के साथ मिलकर नकली वित्तीय प्लेटफॉर्म्स को ट्रेस करना चाहिए और संपत्तियों को फ्रीज़ करना चाहिए ।

5. सामुदायिक निगरानी और रिपोर्टिंग

1. नागरिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे संदिग्ध सामग्री की रिपोर्ट करें:

2. साइबर अपराध पोर्टल: https://cybercrime.gov.in

3. RWA और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे डीपफेक को पहचान सकें और रिपोर्ट कर सकें।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे मजबूत फ़ायरवॉल है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक्सेस मटेरियल की निकासी एवं अन्य चोरियों की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मांग की गई जांच

परिवहन विशेष न्यूज

"उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में पिछले कुछ वर्षों में हुई एक्सेस मटेरियल (स्क्रैप, पिग आयरन, स्टील प्लेट्स, राखड़ आदि) की निकासी और अन्य चोरियों की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यहां केवल परिवहन सिंडिकेट ही नहीं बल्कि कुछ ट्रेडर्स एवं अंदरूनी कर्मचारियों की मदद से ही यह संभव हो पा रहा है 1 ट्रक ट्रांसपोर्टर्स के हितों की रक्षा करने वाले इस मोर्चे की ओर से जारी इस विज्ञप्ति में रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन घटनाओं का विवरण दिया जा रहा है, जो संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है। डॉ. यादव ने मांग की है कि केंद्र सरकार और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराए तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि ट्रांसपोर्टर्स और संयंत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।

राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अंतर्गत राउरकेला में स्थित है और सेल की एक प्रमुख इकाई है, में एक्सेस मटेरियल की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये घटनाएं न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि संयंत्र की उत्पादकता और सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। नीचे रिकॉर्ड अनुसार प्रमुख घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण दिया गया है जिसमे जनवरी 2020 मे स्टील प्लेट्स की चोरी - राउरकेला पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें दो सेंट्रल इंडसट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) कर्मी शामिल थे। ये आरोपी क्रेन ऑपरेटर के साथ मिलकर आरएसपी से स्टील प्लेट्स चुरा रहे थे।जनवरी 2020: स्क्रैप चोरी में सीआईएसएफ जवान निलंबित - दो सीआईएसएफ जवान स्क्रैप मटेरियल की चोरी में शामिल पाए गए और उन्हें निलंबित किया गया। यह घटना संयंत्र की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाती है।दिसंबर 2019 मे मिनरल्स की चोरी और सीआईएसएफ निलंबन - आरएसपी से मिनरल्स की चोरी की घटनाओं के बाद चार सीआईएसएफ कर्मियों को निलंबित किया गया। न्यू प्लेट मिल के पास दो भारी वाहनों को जब्त किया गया था, जो अनधिकृत रूप से प्रवेश कर चुके थे व बिना किसी उचित कार्रवाई के ही निचले स्तर के व्यक्तियों पर नाम मात्र कार्रवाई कर फाइल को बंद कर दिया गया।अक्टूबर 2018 मे पिग आयरन की चोरी - आरएसपी के एक शिपिंग ऑफिसर और क्रेन ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया, जो एक निजी फर्म के साथ मिलकर पिग आयरन की अतिरिक्त लोडिंग कर चोरी कर रहे थे। चोरी की गई मात्रा 6.22 टन थी, जिसकी कीमत लगभग 1.79 लाख रुपये थी। मार्च 2025 मे स्क्रैप डीलर गोदामों पर छापा - प्लांट साइट पुलिस ने स्क्रैप डीलर गोदामों पर छापेमारी की और तीन डीलरों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी आरएसपी से चोरी किए गए स्क्रैप को बेच रहे थे।जुलाई 2025 मे आयरन स्क्रैप स्मगलिंग सिंडिकेट - प्लांट साइट पुलिस ने एक संगठित गिरोह को पकड़ा, जो मोटरसाइकिल चोरी और आयरन स्क्रैप स्मगलिंग में शामिल था। सात आरोपी गिरफ्तार किए गए और नौ प्रमुख चोरी के मामलों का खुलासा हुआ। मई 2025 मे स्क्रैप मटेरियल की अवैध परिवहन - बॉन्डामुंडा पुलिस ने 640 किलोग्राम चोरी किए गए स्क्रैप से लदे एक ऑटो को जब्त किया। यह घटना एक्सेस मटेरियल की निकासी के दौरान हुई थी।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आरएसपी में चोरियां संगठित रूप से हो रही हैं, जिसमें आंतरिक कर्मी, सुरक्षा बल और बाहरी गिरोह शामिल हैं। डॉ. राजकुमार यादव ने कहा, ₹ट्रक ट्रांसपोर्टर्स सारथी की राउरकेला इकाई इस संयंत्र पर निर्भर हैं, लेकिन लगातार चोरियां हमारी आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। हम मांग करते हैं कि ई डी या सीबीआई स्तर की जांच हो और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाए।₹ जिससे परिवहन सिंडिकेट, कुछ ट्रेडर्स व इससे जुड़े अन्य कि बीते 4 वर्षों के आए को खंगाला जाए वह अनधिकृत तरीके से प्राप्त धन को जप्त करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए 1 मोर्चा इन मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल आंदोलन करते हुए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए माननीय मंत्री महोदय - इस्पात मंत्रालय व अन्य उच्च पदासीन पदाधिकारियों से मिलकर जरूरी दस्तावेज प्रदान करेगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

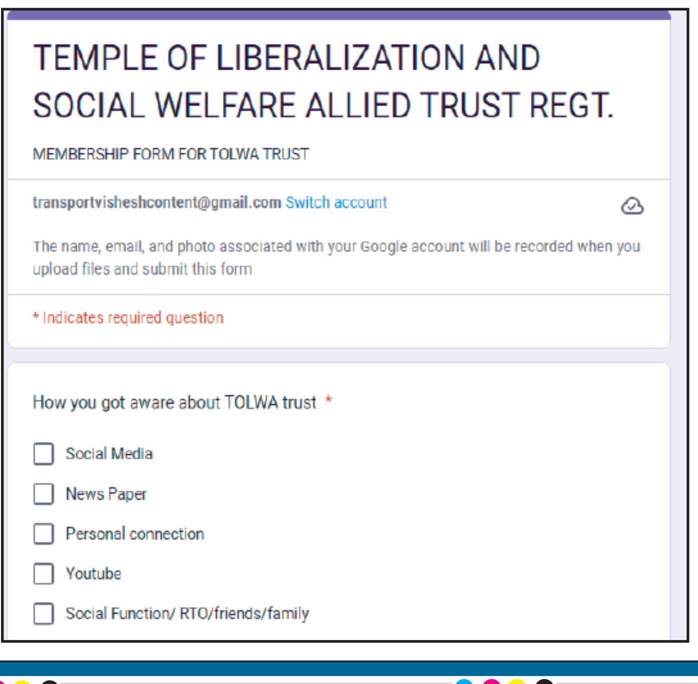
TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.
MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST
transportvisheshcontent@gmail.com Switch account
The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form
* Indicates required question
How you got aware about TOLWA trust *
- [ ] Social Media
- [ ] News Paper
- [ ] Personal connection
- [ ] Youtube
- [ ] Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

श्रीमान भागवत की पहेलियाँ (आलेख : सवेरा, अनुवाद: संजय पराते)

दोहरेपन का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तीन दिन (26-28 अगस्त, 2025) अपने संगठन को एक राष्ट्रवादी, उदार, समावेशी और अहिंसक संगठन के रूप में प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से बिताए, जो केवल यही चाहता है कि भारत पूरी मानवता को शांति और समृद्धि के युग में ले जाए। यह अवसर अगले महीने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एक व्याख्यान का था। इस विशाल समागम में सावधानीपूर्वक चयनित विनम्र श्रोता उपस्थित थे, जिसमें राजधानी के बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और कुछ राजनैतिक दलों के आमंत्रित सदस्य आदि शामिल थे।

भागवत ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए – भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है ; यह पहले से ही अखंड भारत भी है ; भारत के सभी निवासी, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, 'हिंदू' हैं, बशर्ते उनमें मातृभूमि, संस्कृति और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा हो ; और, हिंदू धार्मिक नेताओं ने 1972 में ही उडुपी सम्मेलन में घोषणा कर दी थी कि हिंदू धर्म में जाति-आधारित भेदभाव का कोई स्थान नहीं है और सभी लोग इसके विरुद्ध हैं। यह सब समावेशिता, सहिष्णुता और मानवता की भावना से ओतप्रोत था।

क्या भागवत व्याख्यान के शीर्षक के अनुसार एक आरएसएस के एक नए दृष्टिकोण का या ₹नए क्षितिज₹ का उद्घोष कर रहे थे ? या यह भारतीयों के उस बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोई चाल थी – जिसमें हिंदू भी शामिल हैं – जो आरएसएस की एक सदी की ₹सेवा₹ और ₹बलिदान₹ के बाद भी उसका समर्थन नहीं करते? या यह सिर्फ़ आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व की भ्रमित सोच थी, जो इतने लंबे समय से अपने कट्टर सिद्धांतों को छिपाकर मोदी के नेतृत्व वाले शासन को कायम रखने में मदद करने की कोशिश कर रहा है ? इसका उत्तर आंशिक रूप से तीसरे दिन की कार्यवाही में, जो एक सुनियोजित प्रश्नोत्तर सत्र था, और भागवत के अन्यत्र दिए गए भाषणों में, और वास्तव में, संघ परिवार की गतिविधियों में पाया जा सकता है। आइए इन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करें।

अपने ही आख्यान को फुस्स करते हुए

तीसरे दिन के प्रश्नोत्तर सत्र में, भागवत को सभ्यतागत आकांक्षाओं के दुर्लभ धरातल से हटकर देश के रोज़मर्रा के मामलों में हाथ डालना पड़ा। इस प्रक्रिया में, सच्चाई सामने आ गई।

उदाहरण के लिए, जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल को 'मुक्त' कराने की माँगों के प्रति संघ के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया, तो भागवत ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू करने का खुला मौसम घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हालाँकि आरएसएस स्वयं इन आंदोलनों में शामिल नहीं होगा (जैसा कि उसने राम जन्मभूमि आंदोलन में किया था), लेकिन उसके सदस्य ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उन्होंने कहा, ₹राम मंदिर हमारी माँग थी और हमने उस आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन संघ अब अन्य आंदोलनों में भाग नहीं लेगा। फिर भी, हिंदू जनमानस में काशी, मथुरा और अयोध्या का गहरा महत्व है -- दो जन्मभूमि हैं, एक निवास स्थान है। हिंदू समाज के लिए यह आग्रह व्यक्त करना स्वाभाविक है।₹

एक ही झटके में उन्होंने संविधान, देश के कानून और न केवल अपने नेतृत्व वाले संगठन, बल्कि उस पूरे हिंदू समुदाय, (जिसके बारे में उनकी यह गलत समझ है कि आरएसएस उनका प्रतिनिधित्व करता है) के प्रति अपनी समावेशी-सहिष्णु-मानवता की प्रतिबद्धता की सारी बातों को ध्वस्त कर दिया। पूजा स्थल अधिनियम, 1991, धार्मिक स्थलों के स्वामित्व के प्रश्न को फिर से खोलने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है और कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था, वैसा ही रहना चाहिए। फिर भी भागवत वही पुराना तर्क देते हैं कि अगर हिंदू कुछ चाहते हैं, तो उनकी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए। वे आरएसएस सदस्यों को सावधानीपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति भी देते हैं। यह सर्वविदित है -- और आरएसएस भी इसे स्वीकार करता है -- कि विश्व हिंदू परिषद जैसे विभिन्न संबद्ध संगठन, ऐसे संबद्ध संगठनों में प्रमुख पदों पर बैठे उसके कुछ सदस्यों के माध्यम से, व्यावहारिक रूप से आरएसएस के निर्देशों पर चलते हैं। वास्तव में, हर साल एक समन्वय बैठक होती है, जिसमें सभी 32 संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधि और पूरा आरएसएस नेतृत्व अपनी गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य की कार्ययोजना बनाने के लिए शामिल होता है। इस वर्ष, जब आप यह पढ़ रहे हैं, यह बैठक जोधपुर में हो रही है। इसमें विहिप के नेताओं के साथ-साथ अन्य लोग भी उपस्थित हैं। तो, भागवत मूलतः इन संगठनों को हरी झंडी दे रहे हैं।

जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने यह विचित्र दावा किया कि प्रति दंपत्ति तीन बच्चे संतुलन बनाए रखने के लिए वांछित मानदंड हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण और घुसपैठ जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं। इसके

पीछे क्या तर्क है ? यह फिर से उस सौ साल पुरानी कहावत की ओर संकेत है कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। इसी वजह से आरएसएस हमेशा जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के प्रति सतर्क रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हिंदू तो चुपचाप नियंत्रण अपना लेंगे, जबकि मुसलमान नहीं। सच कहें तो, भागवत ने स्वीकार किया कि वर्तमान में, मुस्लिम प्रजनन दर भी अन्य समुदायों की तरह गिर रही है, और तेज़ी से गिर रही है, लेकिन वह आरएसएस सदस्यों के मन में बैठाए गए गहरे और निराधार भय को दूर करने में असमर्थ थे कि मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल जाएँगे। घुसपैठ के सवाल पर, यह पूछा गया कि अगर ₹अखंड भारत₹ में रहने वाले सभी लोगों का ₹डीएनए₹ एक जैसा है -- जैसा कि उन्होंने पहले दावा किया था -- तो फिर प्रवासियों को क्यों रोका जाए ? भागवत को इसका जवाब देने के लिए ₹देश के कानून की रक्षा₹ के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ा और कहा कि उन्हें अवैध रूप से नहीं आना चाहिए। (याद रखें : काशी और मथुरा जैसे अन्य मामलों में, कानून की रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है !) बेशक, उन्होंने इस तथ्य पर कुछ नहीं कहा कि हाल ही में देश भर में दर्जनों जगहों पर बंगालियों को आरएसएस के दुष्प्रचार से प्रेरित लोगों द्वारा रोहिंग्या या बांग्लादेशी होने के नाम पर परेशान और प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम, मुस्लिमों को छोड़कर, पड़ोसी देशों से आने वाले सभी प्रवासियों को नागरिकता देने के काम में तेज़ी लाता है। भागवत इस सब के मुस्लिम-विरोधी स्वरूप पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह लगातार पर्दाफाश होता जा रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में आरएसएस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर, भागवत ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन उन्होंने यह कहकर इसमें सुधार किया कि अगर कुछ हिंदू "मानसिक संताप" के कारण इस तरह की हरकतें करते हैं, तो यह गलत है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से हिंदू अपनी पीड़ा या क्रोध का प्रदर्शन कर सकते हैं और मस्जिदों को ध्वस्त करके या गोमांस खाने की किसी निराधार अफवाह के आधार पर, मॉब लिंचिंग जैसी अन्य पाशविक हिंसा में लिप्त होकर इसे व्यक्त करते हैं – तो इसे आरएसएस द्वारा बस एक करारा तमाचा ही मानना चाहिए। संयोग से, मांसाहार के बारे में एक सवाल पर भागवत ने कहा कि कोई क्या खाता है, उससे किसी को आहत नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "ज़रूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें ; तब कानून को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी"। इसका मतलब है कि मुसलमानों को तथाकथित हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए – अन्यथा कानून-व्यवस्था का मुद्दा पैदा हो जाएगा।

यह विशिष्ट मुद्दों पर आरएसएस की सोच को शामिल करने का एक और उदाहरण है, जबकि वे यह भी दावा करते हैं कि आरएसएस समावेशिता का समर्थन करता है और किसी के प्रति असहिष्णुता नहीं रखता। शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ₹मूल्यों का पोषण करना और व्यक्ति को सच्चा मानव बनाना है। हर जगह, हमारे (अर्थात हिंदू) मूल्य और संस्कृति सिखाई जानी चाहिए...चाहे मिशनरी स्कूल हों या मदरसे।₹ इसलिए, 'मूल्यों' और 'मानवता' के नाम पर जो पढ़ाया जाएगा, वह हिंदू 'संस्कृति' है। उन्होंने इसी राह पर चलने के लिए मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति की सराहना की।

इस तरह, भागवत के विचारों ने स्वयं ही सच्चाई उजागर कर दी है – 'धर्म' और देशप्रेम आदि की सारी बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ़ खोखली बातें थीं – कटु सत्य यह है कि आरएसएस अपने सदियों पुराने उस एजेंडे को आगे बढ़ाता रहेगा, जो राष्ट्र, आस्था और जनता के बारे में उसकी मध्ययुगीन और प्रतिगामी समझ पर आधारित है। ये बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ़ आलोचनाओं को शांत करने और ज़्यादा भोले-भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए थीं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बातें हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

अनसुलझी दुविधाएँ

जाति व्यवस्था एक सबसे बड़ी पहेली है, जिसे न तो भागवत और न ही उनके पूर्ववर्ती सुलझा पाए हैं। यह एक अनसुलझी समस्या क्यों है और आरएसएस नेता अक्सर इसमें उलझते और रास्ता तलाशते क्यों दिखाई देते हैं ?

आरएसएस का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, उनमें ₹आत्मविश्वास₹ की भावना जगाना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जो प्राचीन हिंदू सिद्धांतों, जिन्हें सनातन धर्म भी कहा जाता है, पर आधारित हो। बहरहाल, वास्तविक जीवन में, यह जातियों और उपजातियों के उस निराशाजनक विभाजन से टकराता है, जो हिंदू समाज व्याप्त है। आरएसएस ने दोनों नावों पर सवार होने की निरर्थक कोशिश की है और लगातार असफल रहा है। अगर कोई सांप्रदायिक मुद्दा है, तो वे किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की एकता बनाने में सफल हो सकते हैं, आमतौर पर इस मुद्दे के जोखिम भरे काम तथाकथित निचली जातियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अचानक जातिगत भेदभाव का मुद्दा उभर आता है -- ऐसा होना ही है -- और यह एकता हवा में उड़ जाती है ; सामाजिक समूह आपस में भिड़ जाते हैं। मोदी और भाजपा के सत्ता में आने के साथ, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जाति-आधारित दलों के नेताओं को आगे बढ़ाने पर निर्भरता बढ़ रही है। वास्तव में, भागवत ने स्वयं इसे विभिन्न जातियों के नेताओं को उभरने के लिए प्रोत्साहित करने के एक तरीके के रूप में सराहा है। लेकिन हमेशा, ये जातिगत गठबंधन हिंदू वर्चस्व के आरएसएस समर्थित उद्देश्य के पीछे लामबंद नहीं पाते। वैचारिक रूप से, आरएसएस नेता अक्सर दो ध्रुवों के बीच झूलते रहते हैं -- उदाहरण के लिए, कभी आरक्षण की आलोचना करते हैं, और फिर कई महीनों तक उसके विरोध में लड़ते रहते हैं।

यह विरोधाभास इसलिए और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आरएसएस के पास जाति-आधारित भेदभाव का कोई ठोस जवाब नहीं है। वह अब भी यही मानता है कि शुरू में 'वर्ण व्यवस्था' श्रम के स्वाभाविक विभाजन के रूप में उत्पन्न हुई थी और यह समाज के लिए मददगार थी। उनके अनुसार, समय के साथ इसमें विकृतियाँ पैदा हुईं। उसने अभी तक इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं किया है कि वर्ण व्यवस्था वस्तुतः गुलामी और बर्बर उत्पीड़न की एक व्यवस्था थी, जो शोषण, हिंसा और उत्पीड़न पर आधारित थी। शुद्धता की अवधारणाएँ और उसके उल्लंघन अंतर्निहित थे। जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि व्यवस्था का विनाश होना चाहिए। किसी दलित के घर कभी-कभार भोजन कर लेना या किसी दलित व्यक्ति से एक गिलास पानी ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह एक भटकाव है, एक चालाकी है। आरएसएस कभी भी जाति-विनाश की माँग नहीं करता, वह कभी जातिगत अत्याचारों के विरुद्ध मुखर नहीं होता, उसकी सरकारें अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिए आबंटित धन भी खर्च नहीं करतीं। इसलिए, वह दलितों को कभी अपने पाले में नहीं ला पाएगा।

इसलिए, जातिगत पूर्वाग्रहों को स्वीकार न करने और उनसे लड़ने की ज़रूरत के बारे में भागवत के दावे, और संघ की उसी के प्रति प्रतिबद्धता, सब बेकार की और ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। असल ज़िंदगी में, आरएसएस आज भी एक उच्च जाति के संगठन के रूप में ही व्यवहार करता देखा जाता है। यह संदेह इतना गहरा है – और वास्तविकता में इतनी जमीनी हकीकत है – कि 2024 के चुनावों में भाजपा/आरएसएस द्वारा संवैधानिक बदलावों की बात करने के प्रयासों को भी मतदाताओं ने नकार दिया, क्योंकि इसे संविधान के संस्थापक बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान माना गया।

व्याख्यानों में व्यक्त भागवत के विचार 21वीं सदी में भारत के सामने मौजूद चुनौतियों के अनुरूप नहीं हैं। उनके पास बेरोज़गारी जैसी आर्थिक समस्याओं के बेहद सरल (उद्यमी बनने के लिए कड़ी मेहनत) समाधान हैं, और वे इस बात से आंख मूंद हुए है कि उनके सहयोगी मोदी ने देश की आर्थिक संप्रभुता को बहुराष्ट्रीय पूंजी के हाथों किस हद तक खतरे में डाल दिया है। जब देश विदेशी पूंजी और उसके घरेलू पिट्ठुओं के हाथों धक्के खा रहा हो, तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे शब्द महज दिखावा हैं। उनके सामाजिक विचार, जैसे कि यह कहना कि हर भारतीय हिंदू है, ज़्यादा से ज़्यादा हास्यास्पद हैं, और भविष्य के लिए एक बुरे सपने का संकेत हो सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

माता-पिता का अहसास...!

माता व पिता का सुखद अहसास,
अपने 'बच्चों' के लिए होता खास।
बहुत ज्यादा उम्मीदें होता आभास,
भविष्य के लिए चिंता होती आस।
वह अपने बच्चे का लालन-पालन,
उन्हें पढ़ाने-लिखाने करें संचालन।

अपना जीवन सन्तान में समर्पित,
बच्चे भविष्य बनाके सब अर्जित।
अपने पैरों पे खड़े कर होते हर्षित,
मुसीबतें आने पे न होते विचलित।
अपने 'सपनों' को यूँ सजाए रखते,
बच्चे को देखे जैसे सितारे चमकते।

संजय एम तराणेकर

बाढ़ प्रभावित गाँवों का भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने किया दौरा, किसानों को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा (ग्रामीण)। आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित गाँवों का भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने सोमवार को दौरा किया और आपदा से प्रभावित किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से समझा। उन्होंने खेतों में जलभराव और फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

उपेंद्र सिंह ने ग्राम बरौली गुजर, तनोरा नूरपुर, कबीस, मेहरा नाहरगंज और सरगनखेरा सहित अन्य गाँवों का भ्रमण कर पीड़ितों से संवाद किया। उन्होंने कहा, ₹प्राकृतिक आपदाएँ जीवन की कठिन परीक्षा होती हैं, लेकिन यदि हम सब मिलकर धैर्य, साहस और सहयोग के साथ आगे बढ़ें, तो हर संकट का समाधान संभव है।"

भाजपा नेता ने यह भी कहा कि सरकार और संगठन स्तर पर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने हेतु व्यापक और निष्पक्ष सर्वे कराए जाएँ, जिससे प्रभावित परिवारों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके।

निरीक्षण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यदुवीर चाहर, रविन्द्र धारिया, डॉ. राजवीर सिंह, डॉ. सी.पी. माहौर, अमरपाल सिंह, अकबर सिंह, पुष्पेंद्र चाहर और जयराम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि हाल ही में आई बाढ़ से इन इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, विशेषकर खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने गंभीर आजीविका संकट खड़ा हो गया है।

तंत्र विद्या में वनस्पतियों का अद्भुत महत्व

भारतीय तंत्र विद्या में वनस्पतियाँ केवल औषधि ही नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने वाले ऊर्जा-स्रोत मानी जाती हैं। जब साधक इन्हें उचित विधि और मंत्र से सिद्ध करता है, तो ये साधना में चमत्कारी परिणाम देती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ, उनके मंत्र और लाभ बताए जा रहे हैं—

१. धतूरा (Datura)

मंत्रः ॐ नमः शिवाय भूतनाथाय धत्तूरं समर्पयामि स्वाहा॥

लाभः भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति, शत्रु नाश, शिव भक्ति में उन्नति।

२. अपामार्ग (Achyranthes Aspera)

मंत्रः ॐ अपामार्गाय नमः॥

लाभः शनि-राहु बाधा निवारण, शत्रु उच्चाटन, ग्रह पीड़ा शांति।

3. अकोण्ठी / विष पौधा (Aconitum Ferox)

मंत्रः ॐ भैरवाय फट्॥

लाभः उग्र साधनाओं में सफलता, अदृश्य शक्तियों से रक्षा।

४. कुटज (Holarrhena)

मंत्रः ॐ कुटजेश्वराय नमः॥

लाभः ग्रहबाधा नाश, पिशाचबाधा से मुक्ति, स्वास्थ्य की रक्षा।

५. भूतकेशी

मंत्रः ॐ कालभैरवाय नमः॥

लाभः भूत-प्रेत व पिशाच बाधा से रक्षा, घर-परिवार में शांति।

६. नागरमोथा

मंत्रः ॐ नागरमोथाय नमः॥

लाभः नकारात्मक ऊर्जा नाश, यज्ञ-हवन में विशेष प्रयोग।

७. अशोक वृक्ष

मंत्रः ॐ अशोकाय नमः॥

लाभः स्त्रियों की पीड़ा शांति, प्रेम और आकर्षण शक्ति वृद्धि।

८. पारिजात (हरसिंगार)

मंत्रः ॐ पारिजाताय नमः॥

लाभः तेज वृद्धि, स्वप्न सिद्धि, अध्यात्म में प्रगति।

९. तुलसी

मंत्रः ॐ तुलस्यै नमः॥

लाभः घर में लक्ष्मी आगमन, रोग शांति, पवित्रता की स्थापना।

१०. बेलपत्र (बिल्वपत्र)

मंत्रः ॐ त्रिनेत्राय नमः॥

लाभः शिव साधना सिद्धि, दरिद्रता निवारण, परिवार में सुख-शांति।

विशेष ध्यान दें:

इन वनस्पतियों को केवल योग्य मुहूर्त में, मंत्रोच्चारण के साथ ही ग्रहण करें। तभी इनमें छुपी हुई दैवीय ऊर्जा प्रकट होती है और यह साधक के जीवन में चमत्कारिक लाभ देती है।

तंत्र विद्या कहती है –

"जब वनस्पति मंत्र से जागृत हो जाती है, तो वह साधक की अदृश्य शक्ति बनकर जीवनभर उसकी रक्षा और सफलता करती है।"

जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द का इलाज

पहला प्रयोग

रात को 15-50 ग्राम मेथी दाना भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी सहित लें l

दूसरा प्रयोग

भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी लें l एक गिलास गुनगुने पानी में 5-10 अदरक रस की बूंदे डाल दें या आधा चुटकी सोंठ और भोजन के बीच बीच में लें l

तीसरा प्रयोग

थल बस्ती करें

सीधे लेट गए और श्वास बाहर छोड़ दें और योनि (शौच जाने की इंद्रिय) को 50 बार अंदर बाहर संकोचन करें l इसी तरह श्वास बार छोड़कर पेट का भी अंदर बाहर संकोचन करें l अंदर ज्यादा, बाहर कम l

इस प्रकार दो- तीन बार करें l

चौथा प्रयोग

सुबह सुबह की धूप घुटनों को लगे इस तरह से बैठे l

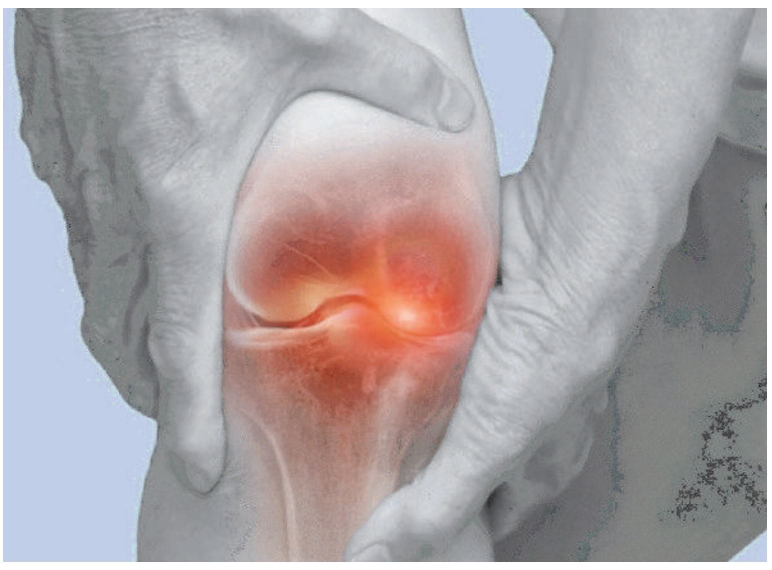

संकल्प स्थापना

यदि हमारे संकल्प सुदृढ़ हों तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता है। महान संकल्प ही महान लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं।

संकल्प के बल पर ही वानरों द्वारा समुद्र पर सेतु की स्थापना हो पायी और संकल्प शक्ति के बल पर ही पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध को जीता गया।

हमारे निर्णय जितनी बार बदलते रहेंगे हमारी सफलता भी उतनी ही प्रभावित होगी। जितना भी सृजन महान व्यक्तियों के द्वारा इस धरती पर हुआ है, वह अनुकूल परिस्थितियों के कारण नहीं अपितु दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ही हुआ है। क्योंकि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो

कभी उन चीजों के बारे में न सोचें; जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली; बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें; जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की हैं।

सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक। सफल लोग अपने मस्तिष्क को इस तरह का बना लेते हैं कि उन्हें हर चीज सकारात्मक व खूबसूरत लगती है।

असल में सफल लोग अपने निरंतर विश्वास से जीतते हैं लेकिन वे असफलताओं से द्वंद्व भी उसी विश्वास से करते हैं। सफलता के लिए विश्वास जीवित रखिये। कल्पना सुंदर होती है, पर उसे जिया नहीं जा सकता है और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता है।

कभी-कभी हमको दिशा बदलने की आवश्यकता होती है, धैर्य सदैव सर्वोत्तम तरीका नहीं होता है। समय की धारा में निरंतर सब कुछ बहा जा रहा है। धन को व्यर्थ करना हमारी इतनी हानि नहीं करता जितना कि समय को व्यर्थ करना।

यह एक ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति फिर किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। मानसिक बोझ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम आंतरिक विकास को खोजने का मार्ग बंद कर देते हैं।

!!!Your Faith can Move Mountains, But Your Doubts can Create Them!!!

आत्मरक्षा में धर्मयुद्ध करना मनुष्य का परम धर्म है

क्या आपका पेट ख़राब है ?

बार बार दस्त आ रहे हैं ?..

बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है ?...

तो इसका सबसे आसान और अच्छा उपचार है, जीरा... !

- आधा चम्मच जीरा चबाके खा लो !
- पीछे से गुनगुना पानी पी लो तो दस्त एकदम बंध हो जाते है एक ही खुराख में.. !

अगर बहुत जादा दस्त हो...

- हर दो मिनिट में आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो आधा कप कच्चा दूध ले लो बिना गरम किया हुआ और उसमे निम्बू डालके जल्दी से पी लो. !
- दूध फटने से पहले पीना है
- और बस एक ही खुराक लेना है

बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाते है।

एक और अच्छा परम्परागत उपाय है....

- ये जो बेल पत्र के पेड़ पर जो फल होते है,
- उसका गुदा चबाके खा लो

पीछे से थोडा पानी पी लो

ये भी दस्त ठीक कर देता है. !

बेल का पाउडर मिलता है बाज़ार में....

- उसका एक चम्मच गुनगुना पानी के साथ पी लो, ये दस्त ठीक कर देता है. !

पेट अगर आपका साफ़ नही रहता और कब्जियत भी रहती है....

तो इसकी सबसे अच्छी देसी दवाई है.. अजवाईन...

- इसको गुड में मिलाके चबाके खाओ और पीछे से गरम पानी पी लो तो पेट तुरंत साफ़ होता है,
- रात को खा के सो जाओ
- सुबह उठते ही पेट साफ होगा. !

एक और अच्छा उपाय है पेट साफ करने का.....

त्रिफला चूर्ण....

- रात को सोते समय एक चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लो पानी के साथ,

पेट साफ हो जायेगा.

- पेट से जुडी दो तीन ख़राब बिमारियां हैं जैसे बवासीर,

पाईल्स,

हेमोरोइड्स, फिसचुला,

फिसर...

- इन सब बीमारियों के लिये सबसे अच्छा है....

मूली का रस.

- एक कप मुली का रस पियो

खाना खाने के बाद दोपहर को या सबेरे.

- पर शाम को मत पीना,
- हर तरह का बवासीर ठीक हो जाता है।
- भगंदर ठीक होता है, फिसचुला और फिसर भी ठीक होता है...

समाजसेवी संस्थाएं लोगों के उत्थान के लिए काम करे: अमर अग्रवाल

सुधा प्रवाह फाउंडेशन ने धूमधाम से मनाई एनिवर्सरी

* सुधा शर्मा ने नि :शुल्क प्रशिक्षण से बदली महिलाओं की जिंदगी

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महिला सशक्तिकरण सहायता फाउंडेशन सुधा प्रवाह ने अपनी पहली वर्षगांठ रायपुर रोड स्थित होटल में धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल थे। एडिशनल एसपी अर्चना झा, हमीदा सिद्दीकी व रोटरी क्लब के पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के उत्थान के लिए काम करे क्योंकि सरकारी योजनाएँ तो सरकार के हिसाब से चलती हैं। एक अरसे से समाजसेवी संस्थाएं लोगों की सेवा करती आ रही हैं। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई तथा महिला सशक्तिकरण के वर्षभर के कार्यों को प्रोजेक्टर पर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्वेता सिंह ने किया।

समाजसेवी सुधा शर्मा वर्षो से महिलाओं को सिलाई, मेहंदी, केक मेकिंग, टोकरी बनाना व झाड़ू निर्माण जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि कई महिलाएं हुनरमंद होते हुए भी उचित मार्गदर्शन व प्लेटफॉर्म की कमी से सीमित रहती थीं। इसी सोच के साथ उन्होंने निःशुल्क प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शुरू किया, जिससे दर्जनों महिलाएं आज अपने रोजगार से परिवार का सहारा बन चुकी हैं।

सुधा शर्मा का कहना है, ₹हम सिर्फ व्यावसायिक कला ही नहीं सिखाते, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान की ताकत भी देते हैं। हमारा लक्ष्य है हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा करना।₹

वर्ष भर की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए सुधा प्रवाह महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन ने कई जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना भी बनाई है। सुधा शर्मा के अथक प्रयासों और निःस्वार्थ सेवा के लिए समाज के कई संस्थानों ने उन्हें सराहा है। फिर भी पिछले तीन वर्षों से सरकारी सहायता के अभाव में ये कार्य स्वयं के साधनों से किए जा रहे हैं। सुधा शर्मा का यह संकल्प समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है, जो हर दिन नए आयाम छू रही हैं। सचमुच, सुधा शर्मा जैसे समाजसेवी महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण बनकर उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित कर रही हैं।

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के दौरान

फोर्टिस गुरुग्राम के नेशनल कैम्पेन में 500 से अधिक लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया

- कॉर्नियल अंधता पर जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर, हॉस्पीटल के कॉर्निया रिट्रिवल प्रोग्राम को मजबूत बनाया

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफएमआरआई), गुरुग्राम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा (25 अगस्त – 8 सितंबर) के दौरान 500 से अधिक लोगों ने नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। इस कैम्पेन के दौरान, अन्य वर्षों की तुलना में नेत्रदान का संकल्प करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कॉर्नियल अंधता के बारे में लोगों के स्तर पर बढ़ती जागरूकता और आम जनता की इसमें प्रतिभागिता का सूचक है।

कैम्पेन के तहत, फोर्टिस गुरुग्राम ने एक संगोष्ठि का भी आयोजन किया था जिसमें नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर करने के मकसद से विशेषज्ञों की वार्ता को शामिल किया गया। फोर्टिस आइ इंस्टीट्यूट ओपीडी में नेत्रदान का संकल्प करने के लिए विशेष बूथ लगाए गए थे ताकि इच्छुक लोग तत्काल खुद को रजिस्टर कर सकें। इसके अलावा, फोर्टिस हॉस्पीटल ने एक जेरियाट्रिक पब्लिक हेल्थ इवेंट का भी आयोजन किया था जिसमें सैंकड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने नेत्रदान का संकल्प लिया।

भारत में कॉर्नियल अंधता काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में, हर साल करीब 100,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स की आवश्यकता है, और सीमित उपभोग दरों के चलते लगभग 200,000 डोनर कॉर्निया की जरूरत है (इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेलमोलॉजी, 2023)। वर्ष 2015-2019 के दौरान कराए गए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में नेत्रहीनता का दूसरा सबसे प्रमुख कारण कॉर्नियल अंधता है, और यही वजह है कि इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

डॉ पारुल शर्मा, प्रिंसीपल डायरेक्टर एंड एचओडी, फोर्टिस आइ इंस्टीट्यूट ने कहा, "नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस (एनपीसीबी) के अनुसार, देश में करीब 11 लाख कॉर्नियल अंधता के शिकार लोग हैं और हर साल लगभग 25,000 नए मामले इन आंकड़ों में जुड़ जाते हैं। इस विषय में, जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित कर मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटा जा सकता है। इसके लिए लोगों को नेत्रदान जैसे परोपकारी प्रयास के लिए अपना सहयोग देने की आवश्यकता है। मल्टी-सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पीटल और टर्शियरी रेफरल सेंटर के तौर पर एफएमआरआई इस मिशन को आगे बढ़ाने तथा अपने हॉस्पीटल कार्निया रिट्रिवल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने बताया कि नेत्रदान को विस्तार देने के काम में जुटे डॉक्टरों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां पेश आती हैं। उन्हें इस बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ-साथ इस बारे में समाज में व्याप्त गलत धारणाओं से निपटना पड़ता है और कई बार किसी व्यक्ति द्वारा नेत्रदान के संकल्प की स्वीकृति देने के बावजूद, मृत्यु होने पर उनके परिजनों की ओर से नेत्रदान के लिए स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया जाता है। इसके अलावा, कई तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी अड़चन पैदा करते हैं। कई बार मृत्यु होने के बाद कार्निया रिट्रिवल के लिए उपलब्ध छह घंटे की सीमित अवधि के भीतर आइ बैंकों को सूचित करने में देरी, अस्पतालों में प्रशिक्षित काउंसलर्स तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी इसमें बाधा बनती है।

यशपाल रावत, फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस गुरुग्राम ने कहा, "नेत्रज्योति (विज़न) प्रत्येक व्यक्ति की सबसे प्रमुख इंद्रीय है। फोर्टिस गुरुग्राम में, हम नेत्रहीनों को दोबारा नेत्रज्योति का लाभ दिलाते हुए उन्हें अधिक रोशन और भरपूर जीवन दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कॉर्नियल सर्जन्स और काउंसलर्स की हमारी कुशल टीम के समर्पित प्रयासों की मदद से, हम साइट-रेस्टोरेशन प्रोग्राम को मजबूत बनाते हुए मरीजों एवं उनके परिवारों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं।"

उल्लेखनीय है कि एफएमआरआई द्वारा आयोजित इस कैम्पेन में युवा पीढ़ी ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया कनेक्शन और सोशल इंफ्लुसिंग के चलते, वे डोनर्स एवं रेसीपिएंट्स के बारे में रील्स, पोस्टों, हैशटैग और पर्सनल स्टोरीज़ के माध्यम इस बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी योगदान करते हैं। देखने में आया है कि 18-40 वर्ष की आयुवर्ग के छात्र एवं प्रोफेशनल्स, समाज में बदलाव के वाहक बन रहे हैं और विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉलेजों में अभियानों, प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों के मंचन के अलावा, टेक्नोलॉजी एवं ऐप्स की मदद से संकल्प को अधिक आसान और सभी तक आसानी से पहुंचने वाली प्रक्रिया का रूप दे रहे हैं। उनके प्रभाव के चलते अक्सर उनके अपने परिजनों के लिए ऐसे फैसले लेना आसान होता है और साथ ही, जरूरत के समय भी नेत्रदान को बढ़ावा मिलता है।

संस्थागत स्तर पर, फोर्टिस हॉस्पीटल्स अपने हॉस्पीटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम (एचसीआरपी) को मजबूत बना रहा है। यह प्रोग्राम अस्पतालों में मृत्यु के बाद पात्र एवं इच्छुक डोनर्स के कॉर्नियल टिश्यू रिट्रीवल में मददगार होता है। समय पर कॉर्निया रिट्रिवल के लिए आईसीयू स्टाफ, ग्रीफ काउंसलर्स, और आइ बैंक प्रोफेशनल्स की समर्पित टीम कॉर्नियल नेत्रहीलता से ग्रस्त लोगों की नेत्रज्योति लौटाने में मदद के लिए तैनात रहती है।

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान
संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है— इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है
स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ऐतिहासिक जीत – प्रेरणा कुमारी और मधु सिंह दास ने दिलाया गौरव

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली : कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित मिसेज़ इंटरनेशनल ग्लोबल एंड यूनिवर्सल पेजेंट 2025 में भारत की दो महिलाओं ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर देश का नाम रोशन किया।

बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कुमारी ने मिसेज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर से आईं मधु सिंह दास ने क्लासिक मिसेज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल एम्बेसडर 2025 का खिताब अपने नाम किया।

इसके साथ ही मधु सिंह दास ने अपनी गरुड़ वेशभूषा के लिए 'मोस्ट ओरिजिनल कॉस्ट्यूम अवॉर्ड' भी जीता, जिसमें उन्होंने हिंदू पौराणिक परंपरा की गहराई और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। दोनों विजेताओं ने पहले मिसेज़ इंडिया लेगेसी का खिताब जीता था और इस मुकाम तक पहुँचने में उन्हें अमीशा चौधरी (संस्थापक एवं नेशनल डायरेक्टर, मिसेज़ इंडिया लेगेसी) का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

भारत लौटने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वे अब महिला सशक्तिकरण और सामाजिक पहलों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण है और हर भारतीय महिला को बड़े सपने देखने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है।

विशेष सूचना केवल 60वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में निशुल्क उपचार की विशेष सुविधा

नई दिल्ली। दिनांक 16-06-25 एम्स, नई दिल्ली, में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग विभाग है, जिसे *नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, एम्स, (National Centre for Ageing, AIIMS) कहा जाता है, जो H678+G57, Block D2, Ansari Nagar East, New Delhi, Delhi 110049, (behind South Extension part 2 market) में स्थित है। जो कि लगभग South Extension Metro station से लगभग 1km दूर है। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, एम्स दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग ब्लॉक है।

अपना आधार कार्ड लेकर वहाँ जाएँ और पंजीकरण करवाएँ। MD डॉक्टर आपकी जानकारी लेंगे और जाँच/दवाएँ लिखेंगे।

यदि आपको किसी सर्जरी जैसे विशेष उपचार की आवश्यकता है: आँखों की जाँच: यूरोलॉजी समस्या, तो आपको उसी परिसर में अलग-अलग बिल्डिंग में रेफर किया जाएगा। सभी टेस्ट और दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं।

पंजीकरण के लिए 6 काउंटर हैं और परामर्श के लिए 10 एमडी डॉक्टर आवंटित हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो अधिकतम 2/3 घंटे में आपका इलाज हो जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों को इस बेहतरीन सुविधा का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कृपया इस जानकारी को व्यापक रूप से साझा करने पर विचार करें।

No.E-29/1/2023-ESTT-I-HQ I/12666/2025

जल शक्ति अभियान
भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय
Government of India, Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग : Department of Water Resources, RD & GR
ब्रह्मपुत्र बोर्ड : Brahmaputra Board

बशिष्ठ : गुवाहाटी-29:
Basistha, Guwahati-29
Date. 01.09.2025

Advertisement for recruitment of Assistant Executive Engineer (Civil) in Brahmaputra Board

Online Application is Mandatory (Closing date: 01.10.2025)

Brahmaputra Board invites online applications from eligible graduate Engineers in Civil Engineering for appointment to the post of Assistant executive Engineer (Civil). The post carries pay scale of Level-10 of the Pay Matrix (Rs.56,100 -1,77,500/-) as per the 7th CPC.

2. (a) The recruitment shall be made on the basis of a valid GATE 2024 or GATE 2025 SCORE in the Civil Engineering discipline and Personal Interview. The applications must be submitted within thirty days from the date of publication of this advertisement i.e. **from 02.09.2025 to 01.10.2025 up to 23.59** hrs.

(b) Applications shall be submitted exclusively through the official recruitment portal (https://online.iitg.ac.in/bbrecruit). No other mode of application shall be entertained. Detailed information regarding eligibility conditions, procedure for submission of applications, selection methodology and other terms and conditions shall be available on the recruitment portal. Candidates are advised to go through the instructions carefully before applying.

UNIVERSITY OF MUMBAI
Re-accredited A++ Grade (CGPA 3.65) by NAAC
Category I University Status Awarded by UGC
M. G. Road, Fort, Mumbai- 400 032
ADVERTISEMENT
No. AAQA/ICD/2024-26/907

Applications are invited from the eligible candidates for the following posts on the establishment of the University of Mumbai.

Sr No	Name of the post	Aided/ Unaided	No. of post	Category
1	Director, Innovation, Incubation and Linkages (Statutory Post)	Aided	01	Open
2	Director, Dharmaveer Ananad Dighe Thane Sub-Campus) (Temporary basis)	Unaided	01	Open
3	Director, Charitrakar Padmabhushan Dr. Dhananjay Keer Ratnagiri Sub-Campus (Temporary basis)	Unaided	01	Open
4	Co-ordinator, Vishwabhushan Dr. Babasaheb Ambedkar Model Degree College, Ambadave (Temporary basis)	Unaided	01	Open
5	Co-ordinator, Vijayalakshmi Vishwanath Dalvie Model Degree College, Talere (Temporary basis)	Unaided	01	Open
6	Assistant Professor, (Chemical Engineering, Computer Engineering & Robotics) School of Engineering & Applied Science, Kalyan (Temporary basis)	Unaided	01 Each	Open
7	Deputy Director, Centre for Distance & Online Education (Unaided)	Unaided	01	Open

Interested and eligible candidates are requested to apply for the said posts in prescribed offline forms in three sets of applications within 15 days from date of publications of this advertisement alongwith the demand draft **(Reserved Category Rs.250/- and Open Category Rs.500/-)** drawn in favour of the "**Finance & Accounts Officer, University of Mumbai**" and submit in the Inward Section, Room No. 25, University of Mumbai, Fort, Mumbai – 400 032. The reservation of various categories is as per the existing rules.

Prescribed application forms and details regarding Qualification, Experience and other terms and conditions are available on the University website **www.mu.ac.in.**

The last date for receiving application is Saturday, the **20th September, 2025 at 5.00 p.m.** The applications received after the last date will not be entertained.

Mumbai : 400 032
Date : 5th September 2025
Sd/-
(Dr. Prasad Karande)
REGISTRAR

MAHARAJA AGRASEN BUSINESS SCHOOL
AICTE Approved Institution
Established by Maharaja Agrasen Technical Education Society
Maharaja Agrasen Chowk, Sector 22, Rohini, New Delhi - 110086
MATES

VACANCIES

Maharaja Agrasen Business School (MABS), Delhi/NCR's premier PGDM institute approved by AICTE, Ministry of Education, Govt. of India invites applications from qualified, experienced and result-oriented innovative and tech savvy candidates for the following positions:

- Admission Counselor(s)
- Admission Manager
- Placement Manager
- Digital Marketing Manager
- SEO and SMO Specialist

Interested Candidates are requested to submit a detailed resume to: hr@mabs.ac.in
www.mabs.ac.in

Last date for submission of application:
on or before 20th September 2025
Salary as per industry norms, no bar for deserving candidates

GMU
GUJARAT MARITIME UNIVERSITY
Transitory Campus : At GNLU Campus, Attalika Avenue Knowledge Corridor, Koba, Gandhinagar, Gujarat - 382426 | Ph.: +91 79 23270500 | Email : info@gmu.edu.in

VACANCY ADVERTISEMENT REFERENCE NO.: GMU/2025-26/AFO/276/02

Gujarat Maritime University (GMU) invite applications from interested candidates for the following position on Contractual basis.

Sr. No.	Name of the Post	Scale / Remuneration	No. of Post(s)
01	Assistant Finance Officer	₹ 56,100 - 1,77,500/- (Level-10) 7th CPC	01 (UR)

LAST DATE FOR SUBMITTING : 06th October, 2025

The detailed notification regarding eligibility criteria & application form for the advertised post is available at https://gmu.edu.in/recruitment (GMU)

Ph.: +91 79 23270500 | www.gmu.edu.in

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ
Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Punjab
Institutional Area, Sector 26, Chandigarh-160019, India
Phone: +91-172-2793589/91 | Fax: +91-172-2793589/90, Extn: 400
Email: helpdesk.mgsipa@punjab.gov.in
Web: mgsipa.punjab.gov.in

WALK-IN-INTERVIEW
[No. 7602 dated 09.09.2025]

MGSIPA invites prospective Candidates to appear in walk-in-interview for the purely contractual position as per the details given below:

Sr. No.	Name of the Specialism Centre	No. of positions	Consolidated monthly remuneration
1.	Land Record Expert	1 (one)	Rs. 1,00,000/-
Interview Date Registration Time and Venue		19.09.2025 (Friday), From 9.30 am to 11.00 am Lecture Hall No. 2, First Floor, Convention Centre.	

- For detailed information regarding eligibility criteria, terms and conditions application procedure etc. log onto www.mgsipa.punjab.gov.in

Note: Any corrigendum(s) to this appointment notice shall be published on the above website only.

RO No. 2018/12/2025/26/2983
Sd/-
Director General

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
लिंक रोड नंबर 3, पत्रकार भवन, भोपाल-462003

विज्ञा.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2025/3264 **विज्ञापन** भोपाल, दिनांक : 09.09.2025

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत टेली मानस सेल हेतु संविदा काउन्सलर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु सीमा
1	संविदा काउन्सलर	14	30000/- रुपये प्रतिमाह	Bachelors in Psychology or Social Work (Regular/Distance/Open mode) or Nursing (Regular) from a recognized educational institution. With 2-Years of post UG qualification experience in Mental Health Counselling. Or Masters in clinical Psychology/ Social Work / Sociology/ Psychology from a recognized educational institution in regular/ distance/open mode.	21-40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त जन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2025 की स्थिति में)

आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल http://www.mponline.gov.in एवं http://iforms.mponline.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 09.09.2025 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 27.09.2025 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हे आरक्षित पदों की संख्या (8%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि) 1.5%	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5%	(लोको मीटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ट रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5%
संविदा काउन्सलर	14	3	2	2	1	1	1	2	1	1	0	-	-	1	-

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नि:शक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद नि:शक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग /ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

अपर मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
जी-18440/25 "स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता"

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
Bhadbhada Road, P.O. Suraj Nagar, Bhopal-462044 (M.P.)
Website : www.nja.gov.in, EPABX : 0755-2432500
NJA/Adm./Rect/2025/01 Dated : 06.09.2025

EMPLOYMENT NOTICE

The National Judicial Academy invites applications to fill-up positions as follows :-

S. No.	Name of Post	Pay Scale (in Rs.)	No. of Vacancies
1.	Research Fellow (Group – A)	Level - 10 Rs. 56,100 – 1,77,500/-	01
2.	Manager (Documentation, Communication, Public Relations) (Group – A)	Level - 10 Rs. 56,100 – 1,77,500/-	01
3.	Assistant Accounts Officer (Group – B)	Level - 7 Rs. 44,900 – 1,42,400/-	01
4.	Jr. Steno cum DEO (Group – B)	Level - 6 Rs. 35,400 – 1,12,400/-	01

The eligibility criteria, application form and other terms and conditions are available on Academy website **https://nja.gov.in.** Applications, complete in all respect, should be received by NJA (in Person/by Post/by Courier) in a sealed cover addressed to **"The Registrar (Administration), National Judicial Academy, Bhadbhada Road, Suraj Nagar P.O., Bhopal-462044" latest by 27.10.2025.**

M.P. Madhyam/121943/2025 REGISTRAR (ADMINISTRATION)

तीन साल और तीन पड़ोसी देशों में उथल-पुथल- कुछ कहता है यह पैटर्न

पड़ोस की उथल-पुथल भारत के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि अस्थिरता का धुंआ हमेशा हमारी ओर भी आएगा और अवसर इसलिए कि सक्रिय पड़ोसी नीति से भारत न सिर्फ़ अपने रिश्तों को मज़बूत कर सकता है बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है।

राजेश जैन

पिछले तीन साल में दक्षिण एशिया ने तीन बड़े राजनीतिक संकट देखे—2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल। तीनों जगह हालात इतने बिगड़े कि सत्ता पलट गई और शीर्ष नेता देश छोड़कर भागे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है? क्या यह महज़ संयोग है या फिर एक गहरा पैटर्न बन रहा है?

नेपाल: सोशल मीडिया बैन और जेन-ज़ी विद्रोह

नेपाल में हाल ही में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी 26 अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन लगा दिया। चीन के करीबी एप्स—जैसे टिकटॉक—को छूट मिली। यह फैसला सीधे चीन के प्रति झुकाव और अमेरिकी कंपनियों के विरोध का संकेत माना गया। नेपाल में पहले से ही बेरोजगारी ऊंची थी—2024 की रिपोर्ट के मुताबिक युवा बेरोजगारी दर लगभग 18% थी। इस माहौल में सोशल मीडिया बैन ने आग में घी का काम किया। आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होकर सड़कों पर उतर आया। संसद, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक भीड़ पहुंची और अंततः ओली को इस्तीफा देकर हेलिकॉप्टर से भागना पड़ा।

बांग्लादेश: छात्रों की 'जुलाई क्रांति'

2024 में बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा लागू करने का आदेश दिया। यह फैसला युवाओं को भड़काने वाला साबित हुआ। आंदोलन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले शुरू हुआ। बांग्लादेश में बेरोजगारी दर लगभग 12% है और हर साल लाखों नए ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में निकलते हैं। कोटा फैसले ने उनकी उम्मीदें तोड़ीं। सरकार ने लाठीचार्ज और इंटरनेट शटडाउन किया, जिससे हालात और बिगड़े। जुलाई से अगस्त के बीच झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत शरण लेनी पड़ी। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाई और नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस को सलाहकार नियुक्त किया। यह आंदोलन सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन तक पहुंचा।

श्रीलंका संकट तख्तापलट

2022 में श्रीलंका का संकट सबसे गहरा था। देश पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज़ था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और महंगाई 34% तक पहुंच गई। 63 लाख लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। 31 मार्च को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया, लेकिन प्रदर्शन और फैल गए। जुलाई तक हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास पर धावा बोला। राजपक्षे देश छोड़कर भागे और बाद में सिंगापुर से ई-मेल के जरिए इस्तीफा दिया। महीनों की खींचतान के बाद नई सरकार बनी।

एक जैसा पैटर्न कैसे बन रहा

तीनों देशों की घटनाओं में एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है—युवा वर्ग में नाराज़गी थी और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। संवाद की जगह दमन चुना गया, जिससे गुस्सा और बढ़ा। विदेशी दबाव और हस्तक्षेप रहा। अमेरिका और चीन जैसे देशों ने दोनों ने मौकों का फायदा उठाने की कोशिश की और तीनों देशों में नेताओं का पलायन करना पड़ा।

क्या विदेशी ताकतें शामिल हैं?

हर बार जब छोटे देशों में बड़ा आंदोलन होता है, तो सवाल उठता है—क्या इसमें बाहरी हाथ है? हां, सही है। बाहरी ताकतें मौके का फायदा उठाती हैं और आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय रंग देने की कोशिश करती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा था। नेपाल में भी कहा गया कि अमेरिका ने जेन-ज़ी आंदोलन को सपोर्ट दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन दोनों ही इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। नेपाल के मामले में ओली की चीन-निकटता और अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन से यह साफ दिखा। हालांकि सच यह भी है कि जनता के भीतर असंतोष न हो, तो कोई भी विदेशी ताकत आंदोलन को हवा नहीं दे सकती। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज करना ही इसका असली कारण हैं।

भारत के लिए सबक

भारत के पड़ोस में बार-बार हो रहे राजनीतिक उथल-पुथल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अस्थिरता से न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी असर पड़ता है। पाकिस्तान में सेना का नियंत्रण, अफगानिस्तान में तालिबान, म्यांमार में गृहयुद्ध और अब नेपाल की स्थिति यह बताती है कि पूरा दक्षिण एशिया उथल-पुथल में है। भारत को चाहिए कि वह पड़ोसियों में लोकतंत्र और स्थिरता को मजबूत करने के प्रयास करे। क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगी होगी, तो धुआं हमारे घर तक भी आएगा।

पड़ोस में अराजकता हो तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते

भारत इस संकट को चिंता के साथ देख रहा है। पड़ोस में ऐसे किसी भी संकट का स्वाभाविक ही भारत पर भी असर होता है। यह दो बड़े खतरे पैदा करते हैं। पहला, सुरक्षा से जुड़े संकट। शरणार्थी सीमा पार करके आ सकते हैं, चरमपंथी सुरक्षित जगह ढूंढ सकते हैं और अशांत लोग सीमावर्ती राज्यों में अव्यवस्था फैला सकते हैं। दूसरा खतरा है -आर्थिक दबाव। समृद्ध देश अकसर समूह में विकास करते हैं- युद्ध के बाद का यूरोप, नॉर्डिक देश या आसियान इसका उदाहरण हैं। कारण, पड़ोस में स्थिरता से स्थिर सीमाएं बनती हैं, जिससे सरकारें व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर ध्यान दे पाती हैं। जबकि अशांति से भरा पड़ोस हमेशा एक बाधा साबित होता है। भारत को यह बात हाल के कड़वे अनुभवों से समझ में आ रही है। भारत फिलहाल तो स्थिति पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के उलट, भारत अपने पड़ोसियों की घरेलू राजनीति में दखल नहीं देता। लेकिन यह उसकी उदासीनता नहीं है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने पड़ोसियों की मदद की है। हमने पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया। नेपाल में संविधान परिवर्तन के दौरान हमने सुझाव दिए। श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय अरबों डॉलर की मदद दी। नेपाल में बढ़ती अराजकता के चलते भारत के लिए तीन प्राथमिकताएं सामने आ रही हैं। पहली, रिफ्यूजियों की घुसपैठ रोकना। दूसरी, नेपाल की स्थिरता के लिए मदद करना। और तीसरी, लोकतांत्रिक मजबूती को बढ़ावा देना।

हम यह जान लें कि हर सांस ईश्वर का वरदान है,

जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, ये एक दुर्लभ रत्न की तरह है, जो समय की गर्द में भी अपनी चमक नहीं खोता। जीवन केवल सांसों का व्यापार नहीं, बल्कि भावनाओं, कर्म और विश्वास की महत्वपूर्ण धड़कन है जो हर क्षण हमें पुकारती रहती है। कभी यह सुबह की पहली किरण में मुस्कुराता है, तो कभी शाम की खामोशी में प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है, क्या हम सच में अपने जीवन को जी रहे हैं? या केवल जीने का भ्रम पाले हुए हैं? जीवन का असली सौंदर्य धन, वैभव या पद की सीढ़ियों में नहीं, वह तो निर्दोष मुस्कान बांटना किसी थके हुए मन को सहारा देने और अपने भीतर की रोशनी को जगाने में छिपा है। यह सच है कि समय का हर कण उन रेत के कणों की तरह है जो मुट्ठी से फिसल जाते हैं, पर वही क्षण अमर हो जाते हैं जिन्हें हमने प्रेम और करुणा से जिया। किसी की आंखो के आंसू पोछना, किसी को उम्मीद दे देना और अपनी राहों में विश्वास के दीपक जलाते जाना, यही जीवन के असली धरोहर हैं। जीवन का मूल्य तभी समझ में आता है जब हम यह जान लें कि हर सांस ईश्वर का वरदान है, और हर दिन नया अवसर है आकाश को छूने का। तो आओ, इस क्षण को व्यर्थ न जाने दें, हर मुकाम को अपने लिए और दूसरों के लिए सुंदर मनभावन कविता बना लें और सुख साथ मिलकर इसे गुनगुनाते हुए आगे जीवन पथ पर हंसते हुए चलते रहें,, हर अनुभव को गीत बना दें, क्योंकि जब तक हम जीवन को महसूस करना नहीं सीखते, तब तक उसका अनमोल रहस्य हमें नहीं मिलता।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

टाइपराइटर: संवाद का वह मोड़, जहाँ समय हुआ मूल्यवान

12 सितंबर 1873 को एक ऐसी मशीन ने विश्व पटल पर कदम रखा, जिसने शब्दों को अनुशासित कर मानव संचार को अभूतपूर्व गति और स्पष्टता प्रदान की। टाइपराइटर, जो पहली बार ग्राहकों के लिए उपलब्ध हुआ, केवल एक यांत्रिक यंत्र नहीं था, बल्कि यह समय की बचत, सटीकता और सभ्यता के विकास का प्रतीक बन गया। उस दौर में, जब पत्र महीनों में अपने गंतव्य तक पहुँचते, व्यावसायिक दस्तावेज़ हस्तलिपि की अस्पष्टता में गुम हो जाते, और साहित्यकारों की रचनाएँ लिखावट की सीमाओं से जकड़ी रहतीं, टाइपराइटर ने एक क्रांति रच दी। इसने लेखन को सरल और तेज बनाया, साथ ही विचारों को व्यवस्थित कर उन्हें व्यापक स्तर पर प्रसारित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, कार्लोस ग्लिडन और सैमुअल सौले की वर्षों की अथक मेहनत का फल था। 1868 में शोल्स ने प्रायोगिक टाइपराइटर का पेटेंट कराया, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से जनता तक पहुँचाने में पाँच साल लगे। 1873 में, रेमिंगटन एंड संस, जो मूलतः एक बंदूक निर्माता थी, ने 'रेमिंगटन नंबर 1' टाइपराइटर का उत्पादन शुरू किया। यह मशीन केवल बड़े अक्षरों में टाइप कर सकती थी और इसकी कीमत 125 अमेरिकी डॉलर थी, उस समय की एक मोटी रकम, जो आज के लगभग 3000 डॉलर के बराबर थी। फिर भी, इसकी बढ़ती माँग ने सिद्ध कर दिया कि यह एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। 1900 तक रेमिंगटन ने लाखों टाइपराइटर बेचे, और 1920 तक यह हर बड़े कार्यालय का अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। टाइपराइटर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लेखन का मानकीकरण। हस्तलिपि की व्यक्तिगत शैली और अस्पष्टता को समाप्त कर इसने अक्षरों को एकसमान और स्पष्ट रूप दिया। अब पत्र, अनुबंध और सरकारी दस्तावेज़ हर जगह एकरूपता के साथ पढ़े जा सकते थे। इसने 'फॉन्ट' की अवधारणा को जन्म दिया, जो आज डिजिटल टाइपोग्राफी की नींव है। क्वर्टी (QWERTY) कीबोर्ड लेआउट, जो टाइपिंग बार के जाम होने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि यह आज भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन का आधार बना हुआ है। आँकड़े बताते हैं कि 1880 के दशक तक रेमिंगटन प्रतिदिन 1500 टाइपराइटर बनाने की क्षमता तक पहुँच चुकी थी, जो इस मशीन की अपार लोकप्रियता का जीवंत प्रमाण है।

टाइपराइटर ने प्रशासनिक कार्यों में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। 19वीं सदी के अंत तक, दस्तावेज़ तैयार करने की गति कई गुना बढ़ गई। जहाँ पहले एक पत्र की प्रतिलिपि बनाने में घंटों लगते थे, टाइपराइटर ने इसे मिनटों में संभव कर दिखाया। कार्बन पेपर के उपयोग ने एक साथ कई प्रतियाँ बनाने की सुविधा प्रदान की, जिसने व्यापारिक और सरकारी संचार को तीव्र, विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनाया। उदाहरण के लिए, 1890 तक अमेरिका और यूरोप के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में टाइपराइटर अनिवार्य हो चुका था, जिससे प्रशासनिक त्रुटियाँ 50% तक कम हुईं। विश्वविद्यालयों, अदालतों और व्यापारिक संस्थानों में दस्तावेज़ एकसमान प्रारूप में संरक्षित होने लगे, जिसने व्यवस्था को नया अनुशासन और व्यवसायिकता प्रदान की।

टाइपराइटर का प्रभाव सामाजिक संरचना पर भी गहरा पड़ा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। 1880 के दशक में टाइपिंग को 'स्त्री-उपयुक्त' कार्य माना गया, क्योंकि यह सौम्य, साफ-सुथरा और धैर्य की माँग करता था। 1900 तक, अमेरिका में लगभग 75% टाइपिस्ट महिलाएँ थीं। उस दौर में, जब महिलाओं का कार्यालयों में प्रवेश असामान्य था, टाइपराइटर ने उन्हें 'टाइपिस्ट गर्ल्स' के रूप में एक नई पहचान और सम्मान दिलाया। 1910 तक, अकेले अमेरिका में 80,000 से अधिक महिलाएँ टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, जिसने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मज़बूती दी और सामाजिक स्थिति को उन्नत किया। यह मशीन चुपके से महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई, जिसने असंख्य महिलाओं को कार्यक्षेत्र में प्रवेश का मार्ग दिखाया।

पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में टाइपराइटर ने एक नई गति और स्पष्टता ला दी। अखबारों को ताज़ा समाचार छापने की गति मिली, संपादकों को लेख व्यवस्थित करने की सहजता और लेखकों को स्पष्ट, पेशेवर पांडुलिपियाँ तैयार करने की सुविधा। 20वीं सदी के प्रारंभ में, टाइपराइटर हर लेखक की मेज़ का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उदाहरण के लिए, मार्क ट्वेन जैसे साहित्यकार, जिन्होंने टाइपराइटर पर अपनी कृतियाँ लिखीं, ने इसे रचनात्मक उत्पादकता का अनमोल वरदान बताया। 1920 तक, विश्व के प्रमुख समाचारपत्र कार्यालयों में टाइपराइटर की खटखटाहट सतत गूँजती थी, जिसने समाचार प्रसार को पहले से कहीं अधिक तीव्र और प्रभावी बना दिया।

टाइपराइटर ने न केवल कार्यक्षमता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया, बल्कि मानव मस्तिष्क की सोच और अभिव्यक्ति की गति को भी पुनर्परिभाषित किया। लेखकों को अब अपनी कल्पनाओं को उतनी ही तेजी से कागज़ पर उतारना पड़ता था, जितनी तेजी से टाइपराइटर के कुंजीपटल शब्दों को आकार देते थे। "गति" और "शुद्धता" जैसे शब्द कार्य-संस्कृति के मूलमंत्र बन गए। 1900 के दशक में टाइपिंग स्कूलों का उदय हुआ, जहाँ प्रति मिनट 40-60 शब्दों की टाइपिंग गति को मानक बनाया गया। इसने आधुनिक उद्योग और कार्यालय संस्कृति को समय की कीमत और अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जिसने उत्पादकता को नया आयाम दिया।

इस मशीन ने राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को भी अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। स्वतंत्रता संग्रामों में गुप्त संदेश और प्रचार-पत्र टाइपराइटर की खटखटाहट में ढले। मज़दूर आंदोलनों और छात्र संगठनों ने इसे विचारों के प्रसार का सशक्त हथियार बनाया। खुफिया एजेंसियों ने गोपनीय दस्तावेज़ों को इसके सहारे सुरक्षित किया। टाइपराइटर ने भाषा को भी नया रूप दिया—हस्तलिपि की विविधता और अस्पष्टता को पीछे छोड़ते हुए इसने मानकीकृत लेखन को बढ़ावा दिया, जिसने "शुद्ध लेखन" की अवधारणा को दृढ़ता प्रदान की और वैश्विक संचार को एकसमान बनाया।

आज का डिजिटल युग टाइपराइटर की ही देन है। क्वर्टी (QWERTY) लेआउट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट और कीबोर्ड संस्कृति, ये सभी उसी मशीन की विरासत हैं। 1980 के दशक तक, जब पर्सनल कंप्यूटर ने टाइपराइटर को धीरे-धीरे विस्थापित करना शुरू किया, तब तक यह मशीन विश्व भर में 50 मिलियन से अधिक इकाइयों में बिक चुकी थी। यह डिजिटल क्रांति का अग्रदूत थी, जिसने हमें तकनीक के माध्यम से संवाद का सहज और स्वाभाविक तरीका सिखाया।

इंदौर के हृदय में बसी एक अनमोल विरासत के संरक्षक राजेश शर्मा जी ने टाइपराइटर के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को जीवंत कर दिखाया है। उनकी अद्वितीय संग्रहशाला में भारत, इटली, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान सहित विश्व भर से 300 से अधिक टाइपराइटर शामिल हैं, जिनमें से कई 100 से 130 वर्ष पुराने हैं। मध्य प्रदेश का यह एकमात्र टाइपराइटर संग्रहालय उनके घर में एक जीवंत स्मारक के रूप में स्थापित है, जहाँ हर कोने से इतिहास की खटखटाहट गूँजती है। शर्मा जी का यह प्रयास न केवल टाइपराइटर की विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि डिजिटल युग में नई पीढ़ी को इस यांत्रिक चमत्कार से जोड़ता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

पं. हरप्रसादपाठक साहित्य समिति मथुरा द्वारा को विशाल साहित्यकार सम्मान समारोह 14 सितम्बर को

गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी में होगा भव्य आयोजन

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। गीता शोध संसथान एवं रासलीला अकादमी के ऑडीटोरियम में पं. हरप्रसाद पाठक साहित्य समिति, मथुरा के तत्वावधान में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितम्बर 2025 को 27वां अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मान समारोह एवं नव प्रकाशित पुस्तकों लोकार्पण का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ किया जाएगा।

जानकारी देते हुए पं. हरप्रसाद पाठक साहित्य समिति, मथुरा के संस्थापक-सचिव डॉ. दिनेश पाठक ₹शशिर₹ ने बताया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर 42 साहित्यकारों का सम्मान किया जायेगा।जिनमें 18 साहित्यकारों को वर्ष 2024-2025 के ₹पंडित हरप्रसाद पाठक स्मृति हिन्दी रत्न सम्मान₹, 2 साहित्यकारों को ₹बाल साहित्य भूषण सम्मान₹, 10 साहित्यकारों को ₹बाल साहित्य श्री सम्मान₹, 2 साहित्यकारों को ₹श्री बाबूलाल जैन स्मृति सम्मान₹, 2 साहित्यकारों को ₹श्री शिव नारायण रावत स्मृति सम्मान₹, 2 साहित्यकारों को ₹श्री श्याम श्रोत्रिय स्मृति सम्मान₹, 2 साहित्यकारों को ₹डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव स्मृति सम्मान₹ 2 साहित्यकारों को ₹श्री चन्द्र पाल शर्मा स्मृति सम्मान₹, 1 साहित्यकार को ₹श्रीमती सत्यवती मिश्रा स्मृति सम्मान₹ तथा 1 साहित्यकार को ₹श्री कीर्ति प्रकाश रस्तोगी स्मृति सम्मान₹ एक साहित्यकार से अलंकृत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा और सनातन धर्म एवं संस्कृति विषय पर शोधपत्रों पर केंद्रित उद्बोधन भी विशेषज्ञों द्वारा दिए जायेंगे।समारोह के द्वितीय सत्र में हिन्दी दिवस के उपलक्ष में अखिल भारतीय काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया जायेगा।जिसमें विभिन्न प्रांतों के कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा।साथ ही नव प्रकाशित 09 पुस्तकों का लोकार्पण होगा।

टक्कर मार स्कूली बस के पलटने से कानपुर में पिता पुत्र की मौत, कई घायल

सुनील बाजपेई

कानपुर। तेज रफ्तार स्कूली बस के पलटने से पिता पुत्र की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इसके पहले उसने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। जिसके बाद यह घटना हुई। पुलिस घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराकर घटना की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह यह घटना साढ़-जहानाबाद मार्ग पर हुई।

मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 40 के करीब स्कूली बच्चों को लेकर एक प्राइवेट बस गोपालपुर स्थित स्कूल आ रही थी। इसी दौरान बस ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिर गए और बस ने उन्हें कुचल दिया। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे खड्ड में पलट गई।

हादसे में बाइक सवार पालपुर गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना की मौत हो गई। जबकि, बाइक चला रहा उनका 25 वर्षीय बेटा राजू व बेटी 20 साल की प्रियंका घायल हो गई।

घटना के तुरंत बाद राजू को अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्कूली बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई है। जबकि, राजू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने बताया मौके पर जांच की जा रही है।

वीर रस के युवा कवि राहुल राय बनखेड़ी होशंगाबाद के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर

परिवहन विशेष न्यूज

नर्मदाचल के मोती के अनमोल रत्न वीर रस के कवि राहुल राय जी बनखेड़ी होशंगाबाद का अल्प समय में हम सभी के बीच से देवलोकगमन की इस खबर ने सभी कलमकारो को दुखों के भंवर में आज घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को वीर रस व देशभक्ति से जोड़ें रखने वाले कवि राहुल राय जी ने अपनी सृजनात्मकता से एक देशभक्ति समर्पित रचना में लिखा था कि

आजादी की असली कीमत
लहू है उन दीवानों का
देश की खातिर मिटने वालें
देश भक्त परवानों का
लंदन में जा गरजें ऊधम सिंह
और शेखर से शेर यहां
अशफाक सुभाष भगत सिंह
बिस्मिल से मस्तानों का ।।

ऐसे भाव वैचारिकता के साथ राष्ट्रवाद के बीजों को अंकुरित करते हैं। युवा कवि राहुल राय जैसे कवि जो देशसेवा के साथ जनसेवा को समर्पित थे। और साथ साथ साहित्य जगत में भी नामचीन कवि थे। पुलवामा की घटना पर एक कवि सम्मेलन में उन्होंने अपनी रचना में कहां था कि

भारत माता के सपूत ने जिस
दिन
सीने पर गोली खाई होगी
याद करो उस रात उसकी मां
को
नींद कैसे आई होगी ।

ऐसे वीर रस के कवि

जिनका असमय निधन पर हम सभी नमर्दाचल परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उनकी रचनाएं उनका वहां वीर रस हमेशा हम सभी को देशभक्ति व देशप्रेम की अलख जागने में सहायक होगा। हम सभी मध्यप्रदेश कलमकारो में रुपेन्द्र गौर, मदन तन्हाई, मनोज साहू, मयूर मालवीय, कमलेश

नागवंशी, सुशील गौर, ब्रिजेश त्रिवेदी, मोहन झलिया, सुनील गौर, अयाज खान, प्रदीप शर्मा, राम वल्लभ गुप्ता, प्रकाश हेमावत, नवीन निश्चल, हरिहर सिंह चौहान आदि सभी नर्मदाचल समूह द्वारा दिवंगत आत्मा के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शत शत नमन किया।

भारत माता की जय के साथ सभी ने वीर रस के देश सेवक कवि राहुल राय जी को प्रणाम किया।

जय हिन्द ।।

नर्मदाचल समूह के सदस्य
हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

नेपाल सहित पड़ोसी मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभावः-एक गहन विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर दक्षिण एशिया आज विश्व राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। नेपाल, जो भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक औरभौगोलिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन, युवा आक्रोश, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, बाहरी हस्तक्षेप और आर्थिक चुनौतियाँ इससंकट की मुख्य वजहें हैं ?भारत के लिए यह स्थिति केवल पड़ोसी की चिंता नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई स्थिरता, आर्थिक व्यापारिक हित और क्षेत्रीय रणनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई है।भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगती है। यह भौगोलिक निकटता दोनों देशों के संबंधों को विशेष बनाती है। नेपाल के लगभग 80 लाख नागरिक भारत में कामकाज और रोजगार से जुड़े हुए हैं।यह केवल आर्थिक पहलू नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन भी है, क्योंकि लाखों नेपाली परिवार भारत में बसते हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते भी आम हैं।भारत के लिए नेपाल में राजनीतिक स्थिरता इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि वहाँ लगातार सत्ता संकट, विद्रोह या गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका सीधा असर भारत की सीमाओं, सुरक्षा और आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा, जो रेखांकित करने वाली बात है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, नेपाल सहित पड़ोसी मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभावः-एक गहन विश्लेषण।

साथियों बात अगर हम, नेपाल के युवाओं के स्पष्ट रूप से खुलासा करने की करें तो उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़, लूटपाट और हथियार छीनने जैसी घटनाओं में उनका कोई हाथ नहीं है। यह काम कुछ बाहरी तत्वों का है, जिन्होंने आंदोलन में प्रवेश करके उसकी दिशा बदलने की कोशिश की। इस बयान से यह साफ है कि नेपाल का युवा वर्ग केवल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है, न कि अराजकता और हिंसा।भारत के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है। अगर नेपाल में लंबे समय तक चुनाव टाले जाते हैं और स्थिर सरकार नहीं बनती, तो अराजक तत्व और बाहरी शक्तियाँ स्थिति का फायदा उठाकर भारत की सीमाओं में असुरक्षा फैला सकती हैं।

साथियों बात अगर हम भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्ते अति गहरे होने की करें तो, नेपाल के कुल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ होता है।भारत नेपाल को मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और औद्योगिक वस्तुएँ भारी मात्रा में निर्यात करता है, जबकि नेपाल से मुख्य रूप से तैलीय बीज, वन उत्पाद और कुछ सीमित वस्तुएँ ही आयात करता है।इससे भारत का ट्रेड सरप्लस बढ़ता है, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। राजनीतिक संकट से नेपाल की अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी, जिससे उसकी खरीद क्षमता घटेगी और भारत के निर्यात पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ व डिजिटल डेटा पॉलिसी जैसे मुद्दों पर तनाव चलनें की करें तो, ऐसे समय में भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाज़ारों की आवश्यकता है। नेपाल भारत का प्राकृतिक और पारंपरिक बाज़ार रहा है।यदि नेपाल की अर्थव्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता के कारण और कमजोर हो जाती है, तो यह भारत की रणनीति के लिए दोहरी चुनौती होगी।यानें एक ओर अमेरिका से तनाव, और दूसरी ओर नेपाल का संकट, दोनों मिलकर भारत की निर्यात नीति, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

साथियों बात अगर हम इसे चीनी दक्षिण एशिया और वैश्विक संलग्नता के एंगल से देखे तो, नेपाल की अस्थिरता केवल भारत का मामला नहीं है। इस क्षेत्र में चीन भी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करनेकी कोशिश करता रहा है।चीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत नेपाल को इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऋण के जाल में फँसाने का प्रयास कर रहा है। अगर नेपाल लंबे समय तक अस्थिर रहता है, तो चीन वहाँ अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेगा।भारत के लिए यह सुरक्षा दृष्टि से खतरा है, क्योंकि नेपाल की खुली सीमा भारत की रक्षा नीति के लिए चुनौती बन सकती है।नेपाल की अस्थिरता केवल सीमाई समस्या नहीं पैदा करेगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अविश्वास और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है। यह स्थिति सार्क जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं की निष्क्रियता को और गहरा करेगी।साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंध, भारत-श्रीलंका संबंध और भारत- भूटान संबंध भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति पर एक प्रकार का डोमिनो प्रभाव पड़ता है।

साथियों बात कर हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लोकतंत्र और न्याय के महत्व की करें तो, 10 सितंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के संवैधानिक और राजनीतिक संकट पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ₹प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस₹ की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नेपाल के हालात पर चिंता जताई है, प्रेसडिंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान कांस्टीट्यूशन बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टसि ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है, पड़ोसी देशों की ओर देखिए, नेपाल में हमने देखा, इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, और बांग्लादेश में भी, पड़ोसी देशों का जक्रि क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संविधान को लेकर विवाद जारी हैं, नेपाल में हालात ऐसे बन गए हैं कजिनता के गुस्से की वजह से प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा है, चार दनि से देश में आग लगी हुई है, बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले ऐसे ही हालात बने थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।हमें क्यों है गर्व?भारत का संविधान दुनियाँ के सबसे बड़ा और सबसे लोकतांत्रिक संविधान में से एक है, इसने न केवल जनता को बराबरी और अधिकार दिए हैं, बल्कि सत्ता में बैठे नेताओं को भी सीमाओं में रहने का सबक सिखाया है, आपातकाल जैसी स्थिति में भी लोकतंत्र ने अपनी राह बनाई और जनता ने संविधान के जरिए ही सत्ता को पलट दिया, न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए संविधान की आत्मा को मजबूत बनाए रखा है।सीजेआई की टिप्पणी इसी भरोसे की ओर इशारा करती है कि चाहे कितने भी संकट आएं, भारतीय लोकतंत्र अपने संविधान की वजह से बार-बार मजबूत होकर खड़ा हुआ है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक स्तरपर सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म और जनआंदोलन की जटिलता की करें तोआधुनिक युग में राजनीति केवल सड़कों और संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। विश्वभर के उदाहरण, फ्रांस में पीली जैकेट आंदोलन, आज 10 सितंबर 2025 को फ्रांसमेँ जबरदस्त आंदोलन, श्रीलंका में राजपक्षे सरकार का पतन, बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं का विद्रोह, यह साबित करते हैं कि सोशल मीडिया जनमत को जिस तरह आकार देता है, वह कभी-कभी स्थिर लोकतंत्रों को भी अस्थिर बना सकता है। एल्गोरिथ्म की समस्या यह है कि यह संतुलित खबरों की जगह अधिक उग्र, सनसनीखेज और विभाजनकारी सामग्री को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण और असंतोष तेज़ी से फैलता है।भारत को नेपाल के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म के प्रभाव पर गंभीर नियंत्रण और निगरानी नहीं की गई, तो यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा बन सकती है।

साथियों बात अगर हम समाधान की दिशा मेँ कदम बढ़ाने की करें तो-(1) नेपाल में शीघ्र और पारदर्शी चुनाव कराना अनिवार्य है।(2) भारत को नेपाल के साथ कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ मजबूत हों।(3) सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म और बाहरी तत्वों पर सख्त निगरानी जरूरी है।(4) नेपाल की आर्थिक कमजोरी दूर करने के लिए भारत को संतुलित व्यापार नीति अपनानी होगी।(5)क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत, नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच बहुपक्षीय संवाद होना चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नेपाल की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, युवाओं की शांतिपूर्ण आकांक्षा, और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ इस बात को साबित करती हैं कि नेपाल में शीघ्र चुनाव और स्थिर सरकार का गठन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।अगर भारत इस मौके पर सक्रिय और संतुलित भूमिका निभाता है, तो न केवल नेपाल को स्थिरता मिलेगी बल्कि भारत का क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व भी और मजबूत होगा।

शिक्षक सम्मान: सच्चे समर्पण की पहचान और पारदर्शिता की आवश्यकता

सच्चे पुरस्कार का मूल्य उस कार्य में निहित है, जो किसी व्यक्ति ने समाज और समुदाय के लिए किया है। पुरस्कार का असली उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत पहचान या नौकरी बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यह उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, जो समाज में सार्थक बदलाव लाने में सफल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे पुरस्कार समाज के वास्तविक विकास और भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

शिक्षक सम्मान, जो हमेशा से समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त है, आजकल कुछ बदलावों का सामना कर रहा है। शिक्षा के प्रति कुछ शिक्षकों का जूनून और उनका समर्पण वाकई शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है—₹गैर सरकारी संगठन₹ द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने की प्रक्रिया। जहां एक ओर यह कदम सराहनीय है, वहीं दूसरी ओर इसमें पक्षपात और व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का भी असर देखा जा रहा है। विद्यालयों या महाविद्यालयों के प्रिंसिपल द्वारा नाम लेने के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि कुछ मेहनती शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है।

आजकल "गैर सरकारी संगठन" और अन्य संस्थाएं शिक्षक सम्मान समारोहों का आयोजन करती हैं, लेकिन इन आयोजनों में पारदर्शिता की कमी साफ़ तौर पर महसूस होती है। शिक्षक का चयन कई बार पक्षपात या व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर किया जाता है। यह उन शिक्षकों के लिए निराशाजनक होता है, जो वर्षों से अपनी मेहनत और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। ऐसे में उनका मनोबल प्रभावित हो सकता है, और यह उनके कार्यों की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है।

शिक्षक-सम्मान देने वाली संस्थाओं और सरकार को इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। जब पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह जरूरी है कि प्रत्येक स्तर पर पात्रता की जांच की जाए, और यह जांच सिर्फ स्कूल या महाविद्यालय के प्रिंसिपल तक सीमित न हो। इसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और आसपास के निवासियों का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि वे ही उस शिक्षक के वास्तविक प्रभाव को समझते हैं। यह परख पूरे वर्ष भर चलनी चाहिए, ताकि चयन प्रक्रिया में कोई भी भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर मिले।

आज के समाज में पुरस्कार और सम्मान एक प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार हो या महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इन पुरस्कारों का चयन एक निश्चित प्रक्रिया से होता है। शिक्षक को पुरस्कार प्राप्ति के लिए स्वयं आवेदन करना पड़ता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, तस्वीरें, विडियो, विभागीय आख्या, पुलिस वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके बावजूद, बहुत से पुरस्कार इस रूप में प्रचारित होते हैं जैसे यह केवल कार्य के कारण मिले हैं, जबकि असल में इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शिक्षक अपनी व्यक्तिगत पहुंच और प्रभाव का सहारा लेते हैं।

वास्तव में, यह चयन प्रक्रिया इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि पुरस्कार के लिए योग्य शिक्षक स्वयं आगे आएं, क्योंकि पहले जब अधिकारियों द्वारा चयन किया जाता था, तो निष्पक्षता या भाई-भतीजावाद का खतरा बना रहता था। लेकिन यहीं पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। हर नियम और प्रक्रिया को बिगाड़ने वाले लोग हर क्षेत्र में होते हैं। इनकी वजह से कभी-कभी वे लोग पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं जो शायद उतने योग्य नहीं होते, बल्कि उनकी पहुंच और गलत तरीके से पुरस्कार प्राप्त करने की कला उन्हें सफल बना देती है। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक भी कभी-कभी आलोचना का शिकार हो जाते हैं।

यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या सच में हमें पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहिए? मेरी विचारधारा से यह मेल नहीं खाता कि मैं स्वयं पुरस्कार मांगूं। पुरस्कार प्राप्त करना एक सम्मान की बात है, लेकिन क्या उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं आगे आना सही है? एक शिक्षक का असली उद्देश्य अपनी शिक्षा और छात्रों के विकास में योगदान करना होता है, न कि अपनी नौकरी या वेतन बढ़ाने के लिए पुरस्कार प्राप्त करना।

जब हम पुरस्कारों को केवल व्यक्तिगत फायदे के रूप में देखते हैं, तो यह सवाल उठता है कि इस पुरस्कार से स्कूल, बच्चों, समाज और समुदाय को क्या फायदा होता है? क्या इसका कोई वास्तविक प्रभाव समाज में दिखता है, या यह सिर्फ एक सम्मान और पहचान का प्रतीक बनकर रह जाता है? अक्सर हम यह नहीं देख पाते कि पुरस्कार मिलने से स्कूल के बुनियादी ढांचे, विद्यार्थियों की शिक्षा, या समग्र समाज के भले के लिए कुछ ठोस बदलाव आया हो।

जहां तक पुरस्कार की बात है, मैं पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का पूरी तरह सम्मान करती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि पुरस्कार का असली उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। यदि पुरस्कार के माध्यम से किसी स्कूल को बेहतर संसाधन, रास्ता, मैदान, कमरे या कोई अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर पुरस्कार हेतु आवेदन करूंगी, ताकि स्कूल और बच्चों का भला हो सके। लेकिन मैं किसी पुरस्कार के लिए खुद को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, यदि वह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।

सच्चे पुरस्कार का मूल्य उस कार्य में निहित है, जो किसी व्यक्ति ने समाज और समुदाय के लिए किया है। पुरस्कार का असली उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत पहचान या नौकरी बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यह उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, जो समाज में सार्थक बदलाव लाने में सफल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे पुरस्कार समाज के वास्तविक विकास और भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक।

केला : खाएं भी और फैशन भी चमकाएं

चंद्र मोहन

केले का कई तरह से इस्तेमाल होते देखा या सुना है. केले या केले के तने का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले के रेशों का इस्तेमाल अब फैशन इंडस्ट्री में भी होने लगा है, वो भी अलग-अलग तरह के कपड़े तैयार करने में. जो केला अब तक खाने के काम आता था, अब इसका उपयोग ब्रांडेड उत्पाद तैयार करने में भी किया जा रहा है जिसका सीधा असर केले की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति पर दिखेगा. आइए जानते हैं केले के रेशे से कैसे तैयार होंगे ब्रांडेड उत्पाद.

फैशन इंडस्ट्री में जल्द मचेगा तहलका

केले के तने और उनके छिलके में प्राकृतिक फाइबर पाया जाता है जिसका गहनों से लेकर कपड़ों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है. केले के रेशे से बुने कपड़े फैशन की दुनिया में धूम मचा सकते हैं. इस काम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान (एनआरसीबी) शोध कार्य में जुटा है. इसके लिए तो संस्थान ने बाकायदा मुंबई स्थित केंद्रीय कपास तकनीक संस्थान से समझौता किया है. उम्मीद है कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास जल्द ही रंग लाएंगे. रेशे गलाने की प्रक्रिया में सुधार कर उम्दा क्वालिटी के रेशों का उत्पादन करने के लिए एनआरसीबी और केंद्रीय कपास तकनीक संस्थान साथ-साथ मिलकर काम करेगा. केले के रेशों में गैर-हानिकारक रसायनों को मिलाकर लंबे और मजबूत रेशे तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है.

केले के रेशे से बन रहे हैं कपड़े!

वहीं रेशम नगरी भागलपुर में भी अब केले के थंब से निकले रेशे से कपड़े बनाये जा रहे हैं. इस तरह से तैयार किए गए कपड़े नाइजीरिया और केन्या के लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. बंगाल, यूपी, दिल्ली और हैदराबाद से भी ऐसे कपड़ों की मांग है लेकिन विदेशों में ज्यादा कपड़े बिक रहे हैं. हबीबपुर मोमिनटोला, हुसैनाबाद नयाटोला, शाहजंगी, बदरपुर, पुरैनी आदि जगहों पर 50 से अधिक बुनकर हथकरघे पर केले के रेशे के धागे से कपड़े तैयार कर रहे हैं. साथ ही इस रोजगार में 500 से अधिक महिलाएं भी जुड़ी हैं जो रेशे काटकर धागा तैयार कर रही हैं.

केले के रेशे के गुण

भीतरी परत रेशम की तरह मुलायम होती है.

बाहरी परत बर्लेप या कपास की तरह खुरदरी होती है.

रेशमी आंतरिक रेशा बहुत नाजुक होता है.

साथ ही, रेशम की तुलना में इसका उत्पादन अक्सर अधिक महंगा होता है.

चूंकि रेशम पहले से ही ग्रह के सबसे टिकाऊ फाइबर में से एक है, इसलिए केले के फाइबर की दुनिया भर में अधिक मांग नहीं है.

कैसे बनता है केले का रेशे से कपड़ा?

सबसे पहले, केले के छिलके और तने के रेशों को अलग किया जाता है. इस रेशे को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जिसमें रेटिंग भी शामिल है जिसमें रेशों को नरम करने और अलग करने के लिए केले के छिलकों को पानी या किसी रासायनिक पदार्थ में भिगोया जाता है. केले के छिलके के अनुपयोगी हिस्सों को भी काटा जा सकता है लेकिन यह तरीका अधिक मेहनत वाला है. एक बार जब अलग-अलग रेशे प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है और सुखाया जाता है. इस स्तर पर, आंतरिक और बाहरी रेशों को आमतौर पर एक साथ रखा जाता है.

विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

भारत केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु भारत का सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन करने वाला राज्य है जो भारत के कुल उत्पादन का 30% से ज़्यादा उत्पादन करता है और सालाना 80 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा केले उगाता है। राज्य की जलवायु, मिट्टी की किस्म और पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ दक्षिण भारत में केले की बड़ी मात्रा में खेती के लिए अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। तमिलनाडु केले की तीन लोकप्रिय किस्मों का घर है जिनमें रोबस्टा, रस्थली और नेंड्रन शामिल हैं। इन किस्मों का दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किया जाता है।

भारत में कितने केले का उत्पादन होता है?

भारत में हर साल 33 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा केले की खेती होती है, जो पूरे देश में व्यापक रूप से की जाती है। भारत दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। केले की खेती साल भर की जाती है और यह भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय भारतीय किस्मों में ग्रैंड नैने (G-9), पूवन और नेंड्रान शामिल हैं। केले का सेवन हर रूप में किया जाता है, नाश्ते से लेकर पारंपरिक भारतीय मिठाइयों तक।

दुनिया के शीर्ष 7 केला उत्पादक देश

रैंक देश वार्षिक उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)

1 भारत 30.5 - 33
2 चीन 11.7 - 12.1
3 इंडोनेशिया 7.2 - 8.9
4 ब्राज़िल 6.8 - 7.0
5 इक्वेडोर 6.5 - 6.6
6 फिलिपींस 5.9 - 6.4
7 कोलंबिया 2.0 - 3.5

नोट: ये संख्याएँ 2023-2024 के हालिया आंकड़ों पर आधारित हैं जो मुख्य रूप से खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व जनसंख्या समीक्षा से प्राप्त हैं।

भारत : दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत प्रति वर्ष लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन करता है। केले के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के कारण, देश भर में केले उगाए जाते हैं। भारतीय केले मीठे और मुलायम होने के साथ-साथ लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए भी लोकप्रिय हैं। केले भारत भर के कई घरों में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले फलों में से एक हैं और पारंपरिक भोजन, मिठाइयों, धार्मिक प्रसाद आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है।

चीन : चीन दूसरा सबसे बड़ा केला उत्पादक है, जो लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है। केले उगाने वाले विशिष्ट क्षेत्र ग्वांगडोंग, गुआंगशी और युन्नान हैं। चीन में बड़े व्यावसायिक केले के खेत हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और समग्र फसल उपज बढ़ाने के लिए विज्ञान-आधारित कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

क्योंकि गीले होने पर उन्हें अलग करना मुश्किल होता है, अतः एक बार सूख जाने पर, रेशों को गुणवत्ता के आधार पर समूहों में अलग कर दिया जाता है. "ए" समूह में सबसे अच्छे से सर्वश्रेष्ठ रेशे शामिल होते हैं, और इसका उपयोग रेशम-वैकल्पिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है. कुछ निर्माताओं के पास केवल दो समूह हो सकते हैं लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के केले फाइबर ग्रेड का उत्पादन कर सकते हैं. अलग किए गए रेशों को फिर सूत में पिरोया जाता है. धागे का उपचार और रंगाई की जाती है, और इसे वस्त्र, सहायक उपकरण, सजावट की वस्तुओं या औद्योगिक उत्पादों में बुना जाता है.

दुनिया का सबसे बड़ा केला जायंट हाइलैंड केला (Musa ingens) है, जो इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र और इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ में पाया जाता है. यह केला 25-30 सेंटीमीटर लंबा और 3 किलोग्राम तक भारी हो सकता है और इसका पौधा नारियल के पेड़ जितना ऊंचा होता है.

खासियतें:

वैज्ञानिक नाम: मूसा इंगेन्स (Musa ingens)

क्षेत्र: इंडोनेशिया का पापुआ न्यू गिनी द्वीप और पश्चिम पापुआ क्षेत्र

आकार: 25-30 सेंटीमीटर लंबा

वजन: लगभग 3 किलोग्राम तक

पौधे की ऊंचाई: नारियल के पेड़ जितना लंबा

एक और महत्वपूर्ण खोज:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जंगली केलों की एक प्रजाति, मूसा इंडंडामैनेंसिस (Musa ingens), में 4.2 मीटर लंबा फलन (फल-गुच्छ) दर्ज किया गया है जो दुनिया भर में दर्ज सबसे लंबा केले का फल बन गया है. यह खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है.

यह केला बहुत बड़ा और भारी होता है जिसके एक केले में ही किसी व्यक्ति का पेट आसानी से भर सकता है.

नेपाल का लोकतंत्र: पुराने वर्चस्व से नई चुनौती तक

1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद नेपाल ने अब तक 13 प्रधानमंत्री देखे। इनमें 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय रहे। मधेशी, जनजातीय, दलित और महिला समुदाय से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। संसद और नौकरशाही में भी इन समुदायों की भागीदारी बेहद सीमित है। नेपाल की लगभग 35% आबादी मधेशियों की है, लेकिन सत्ता में उनका प्रभाव लगभग नगण्य है। इस पृष्ठभूमि में काठमांडू के मेयर बालेन शाह का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि जातीय असमानता के खिलाफ एक प्रतीकात्मक चुनौती है, जिसे युवा पीढ़ी खुले दिल से अपना रही है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

नेपाल हिमालय की गोद में बसा छोटा-सा देश है। आकार में भले छोटा हो, लेकिन राजनीति और जातीय समीकरण के लिहाज से इसकी जटिलता किसी बड़े देश से कम नहीं। नेपाल पिछले तीन दशकों से लोकतंत्र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लोकतंत्र अब भी अधूरा है। सत्ता और संसाधनों पर एक ही वर्ग का कब्ज़ा है—पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ। संसद से लेकर प्रशासन और सेना तक, हर जगह यही जातियाँ हावी हैं। मधेशी, जनजातीय, दलित और महिलाएँ अब भी सत्ता की सीढ़ियों के निचले पायदान पर खड़ी हैं।

1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई थी। जनता को उम्मीद थी कि अब सत्ता में विविधता आएगी और हर समुदाय को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 1990 से अब तक नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे। इनमें से 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय रहे। यानी 35% मधेशियों की आबादी होने के बावजूद एक भी मधेशी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जनजातीय और आदिवासी समूह संसद में मौजूद हैं, लेकिन उनके नेता केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रहे। दलित और महिलाएँ तो आज भी सत्ता के सबसे हाशिये पर खड़ी हैं। यह तस्वीर बताती है कि नेपाल का लोकतंत्र कितनी गहरी जातीय असमानता से ग्रस्त है। लोकतंत्र के नाम पर चेहरे तो बदले, लेकिन सत्ता का चरित्र वही रहा—ब्राह्मण और क्षत्रिय केंद्रित।

नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही वह नई पीढ़ी है जिसे जनरेशन-Z कहा जाता है। यह सोशल मीडिया, पॉप कल्चर और वैश्विक राजनीति से जुड़ी हुई है। इनके लिए जाति और वंश की राजनीति पुरानी और अप्रासंगिक है। यह पीढ़ी पारदर्शिता चाहती है, समान अवसर चाहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव को केवल सोचती नहीं बल्कि मांग भी करती है। यही कारण है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह आज नेपाल के युवाओं के बीच परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं।

2022 में जब बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता तो यह केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि सत्ता की पुरानी धारणाओं पर सीधी चोट थी। काठमांडू दशकों से मुख्यधारा की पार्टियों—नेपाली कांग्रेस, UML और माओवादी केंद्र—का गढ़ माना जाता था। लेकिन शाह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सबको चौंका दिया। वे न तो परंपरागत राजनीति से आए थे और न ही किसी जातीय वंश से जुड़े थे। उनकी पृष्ठभूमि हिप-हॉप कलाकार और इंजीनियर की थी। वे मधेशी भी हैं और बौद्ध भी। यानी हर लिहाज से नेपाल की मुख्यधारा की राजनीति से बिल्कुल अलग। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि जनता अब विकल्प चाहती है। खासकर युवा पीढ़ी, जो बार-बार जातीय गणित से चलने वाली राजनीति से ऊब चुकी है।

बालेन शाह का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वे सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं और सीधा संवाद करने का तरीका जानते हैं। नेपाल की मौजूदा राजनीति जहाँ अभी भी भाषण और रैलियों पर निर्भर है, वहीं शाह डिजिटल युग की राजनीति कर रहे हैं। उनका संगीत, उनकी स्पष्ट बातें और उनकी स्वतंत्र छवि युवाओं को तुरंत आकर्षित करती है। यह फर्क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में पहली बार कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जो राजनीति को कूल बना रहा है।

लेकिन सवाल यही है कि क्या नेपाल की पुरानी सत्ता संरचना इतनी आसानी से टूट जाएगी? नेपाली कांग्रेस, UML और माओवादी जैसे दल दशकों से सत्ता पर काबिज हैं। इनके नेता ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और इनकी पकड़ प्रशासन, सेना और नौकरशाही तक फैली हुई है। यह पूरा ढांचा बालेन शाह जैसे किसी नेता के लिए दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। संभावना है कि शाह को "अनुभवहीन" या "पॉपुलिस्ट" कहकर खारिज करने की कोशिश की जाएगी। उनकी स्वतंत्र पहचान पर सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठे लोग कभी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते।

अगर नेपाल बालेन शाह जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका देता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक होगा। नेपाल पहली बार किसी गैर-ब्राह्मण/क्षत्रिय प्रधानमंत्री को देखेगा। यह संदेश जाएगा कि लोकतंत्र केवल नाम का नहीं बल्कि वास्तविक रूप से समावेशी है। मधेशी, जनजातीय और दलित समुदाय को यह विश्वास मिलेगा कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। युवाओं को लगेगा कि उनकी आवाज़ मायने रखती है।

लेकिन अगर बदलाव की इस मांग को दबाया गया, तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। युवा पीढ़ी पहले ही अधीर है। वे सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी और सपनों को साझा कर रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ दबाई गई, तो असंतोष सड़क पर आंदोलन में बदल सकता है। नेपाल ने पहले भी जनआंदोलन देखे हैं और इतिहास गवाह है कि जब जनता चाहती है, तो कोई भी सत्ता ढांचा स्थायी नहीं रह पाता।

नेपाल आज दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है, जहाँ सत्ता कुछ जातियों के बीच बंटी हुई है। दूसरी तरफ नई राजनीति है, जो समावेशी, पारदर्शी और युवाओं से जुड़ी है। बालेन शाह इस बदलाव का प्रतीक हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या नेपाल जातीय ढांचे वाली राजनीति से आगे बढ़ पाएगा या नहीं।

अगर नेपाल यह कदम उठाता है, तो वह दक्षिण एशिया में एक मिसाल बन सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी राजनीति अक्सर वंशवाद और जातीय समीकरण में उलझी रहती है। नेपाल अगर इस ढांचे से बाहर निकलता है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा होगी। लेकिन अगर पुरानी सत्ता संरचना कायम रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। युवाओं का भरोसा टूटेगा और यह भरोसा टूटना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है।

नेपाल की राजनीति दशकों से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के कब्ज़े में रही है। लोकतंत्र आया, चेहरे बदले, लेकिन चरित्र वही रहा। आज की पीढ़ी इसे चुनौती दे रही है। बालेन शाह इसका चेहरा हैं। यह पीढ़ी जाति, वंश और सत्ता के पुराने ढांचे को स्वीकार नहीं करना चाहती। नेपाल का लोकतंत्र अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। या तो यह समावेशी होकर सबको बराबरी देगा, या फिर पुरानी असमानता को जारी रखेगा।

भविष्य का फैसला अब नेपाल की नई पीढ़ी के हाथ में है और उनकी मांग साफ है—अबकी बार राजनीति सबकी, सिर्फ ब्राह्मण-छत्री की नहीं।

बाजार जगत व व्यावसायिक वर्ग अलर्ट मोड पर रहें? वित्तमंत्री का सख़्त रुख-कर कटौती का लाभ आम जनता तक पहुंचानें व्यक्तिगत रूप निगरानी का ऐलान!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

भारत की आर्थिक संरचना में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों को ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। 2017 में जब इसे लागू किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था- "एक राष्ट्र, एक टैक्स" की अवधारणा के तहत पूरे देश को एकीकृत करना और कर ढांचे की जटिलताओं को कम करना। अब 2025 में, सरकार ने जीएसटी सुधारों की नई श्रृंखला लागू करते हुए कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की है।यह कदम सीधे तौर पर महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को राहत देने वाला माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कर कटौती का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचेगा? क्या व्यवसायी वर्ग इस राहत को उपभोक्ताओं तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाएंगे? और क्या अंतरराष्ट्रीय दबावों जैसे ट्रंप प्रशासन के 50 पर्सेंट टैरिफ फैसलों का कोई प्रभाव इन सुधारों पर पड़ा है?मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं जीएसटी दरों में कटौती से तुरंत उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कर घटने पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर स्थिति इतनी सरल नहीं होती।बाजार में अक्सर देखा गया है कि व्यापारी या निर्माता अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमतों में उतनी कटौती नहीं करते, जितनी कर दरों में कमी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर पहले 18 पर्सेंट जीएसटी था और अब उसे 12 पर्सेंट या जीरो कर स्लैब में लाया गया है, तो कीमत में 6 पर्सेंट या 18 पर्सेंट की कटौती होनी चाहिए। लेकिन कई बार यह अंतर उपभोक्ताओं तक मात्र 2-3 पर्सेंट ही पहुंचता है। यही कारण है कि आम जनता के मन में भ्रम बना हुआ है कि क्या यह सुधार वास्तव में उनके लिए हैं या केवल उद्योग जगत के लिए।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे जीएसटी सुधार 2025-जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना सबसे बड़ी चुनौती

साथियों बात अगर हम केंद्रीय वित्तमंत्री के 6 सितंबर 2024 को सख्त रुख और निगरानी के ऐलान की करें तो उन्होंने इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से व्यवसायों द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। यह बयान जनता में विश्वास जगाने वाला है, क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीयमंत्री ने इतनी सख्ती से कहा है कि वह लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नजर रखेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि 22 सितंबर के बाद बहुत बड़ा सतर्कता अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर कटौती का असर कीमतों पर दिखे।सरकार ने इस निगरानी अभियान को केवल वित्त मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा है। सांसदों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बाजार दरों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इनको सख़्ती से अगले एक से डेढ़ महीने तक सतत निरीक्षण का काम सौंपा गया है। सीबीआईसी यह देखेगा कि कर कटौती का असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है या नहीं। इस तरह एक बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र बनाया गया है ताकि कहीं भी लापरवाही या हेराफेरी की गुंजाइश न रहे।

साथियों बात अगर हम सरकार के कड़क संदेश की करें तो"लाभ न पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा" स्पष्ट वक्तव्य कि लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बाजार जगत को सीधा संदेश देता है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि व्यवसायिक वर्ग सावधानी बरतेगा और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने में सहयोग करेगा।यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं,बल्कि सरकार की उस गंभीरता का प्रतीक है जो वह जनता को राहत देने के लिए दिखा रही है।

साथियों बात अगर हम उपभोक्ताओं को भी जागृत होने की करें तो,सिर्फ सरकार की निगरानी ही पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना होगा कि वे बाजार में घटे हुए कर दरों का लाभ पा रहे हैं या नहीं। यदि व्यापारी कीमत कम नहीं करता तो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। भारत में उपभोक्ता अदालतें और हेल्पलाइन मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग उनका उपयोग नहीं करते। जीएसटी सुधारों का असली फायदा तभी मिलेगा जब जनता भी सक्रिय होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी।डिजिटल बिलिंग और ई-इनवॉयसिंग व्यवस्था जीएसटी सुधारों को और प्रभावी बनाती है।अब हर लेनदेन की डिजिटल रिकॉर्डिंग होने लगी है, जिससे कर चोरी की संभावना कम होती है। इससे यह भी आसान हो जाएगा कि कर दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता कीमतों में परिलक्षित हो रहा है या नहीं। सरकार को चाहिए कि वह डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर कीमतों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखे।

साथियों बात अगर हम जीएसटी 1.0 से जीएसटी 3.0 तक का सफर की करें तो,वित्त मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि जीएसटी 1.0 (2017) का उद्देश्य राष्ट्र को एकीकृत करना था। इसके बाद जीएसटी 2.0 (2025) का फोकस "सरलता" पर है, ताकि कर ढांचे को आम व्यवसायियों और जनता के लिए आसान बनाया जा सके। उन्होंने संकेत दिया कि जीएसटी 3.0 भविष्य में और भी व्यापक सुधार लेकर आएगा। संभव है कि इसमें पेट्रोलियम उत्पादों और कुछ अन्य जटिल कर ढांचों को भी शामिल किया जाए। इस तरह भारत की कर व्यवस्था धीरे-धीरे अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता- हितैषी बन सकती है।भारत जैसे विशाल देश में महंगाई केवल कर ढांचे की वजह से नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक तेल कीमतों और मौसमी उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करती है। फिर भी कर कटौती से कुछ हद तक राहत मिलना तय है। यदि व्यवसायी वर्ग ईमानदारी से लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए तो दाल, चीनी, पैक्ड फूड, कपड़े और घरेलू उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी देखी जा सकती है। यह सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करेगा।भविष्य की राह, जीएसटी 3.0 से उम्मीदें- विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएसटी 3.0 भारत की कर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसमें न केवल पेट्रोल-डीजल को शामिल किया जा सकता है, बल्कि वर्तमान कर स्लैब को और सरल किया जा सकता है। साथ ही, छोटे व्यवसायियों के लिए अनुपालन की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत का जीएसटी मॉडल विश्व स्तर पर एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष की करें तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य-ट्रंप के टैरिफ से तुलना,कईविशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या ये सुधार ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50 पर्सेंट टैरिफ के मद्देनजर पेश किए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव को संतुलित करने के लिए घरेलू कर सुधार दिखा रही है। लेकिन वित्त मंत्री ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पिछले डेढ़ साल से इन सुधारों पर काम कर रही है और यह प्रक्रिया घरेलू जरूरतों से प्रेरित है, न कि अंतरराष्ट्रीय दबाव से। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की कर नीति को घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं और महंगाई नियंत्रण के नजरिए से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जीएसटी सुधार 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। यह केवल कर दरों में कटौती का मामला नहीं,बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास बनाने का प्रयास भी है। यदि व्यापारी वर्ग ईमानदारी से कर कटौती का लाभउपभोक्ताओं तक पहुंचाए और सरकार निगरानी में सख्ती दिखाए तो यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी यहदिखाएगा कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों और जनताकी भलाई को प्राथमिकता देता है, चाहे वैश्विक दबाव कुछ भी क्यों न हों।आने वाले वर्षों में जीएसटी 3.0 से और भी बड़ी उम्मीदें हैं,और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का भविष्य काफी हद तक इस कर ढांचे की सफलता पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण साक्षरता: जमीनी स्वयंसेवक साक्षरता को कैसे बढ़ा सकते हैं

विजय गर्ग

वे न केवल पढ़ने के सत्रों का नेतृत्व करते हैं और बच्चों को कहानियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान करते हैं जो कक्षाएं अक्सर नहीं कर सकती हैं। स्वयंसेवक अपने पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों को समूहीकृत करके, केंद्रित इनपुट देकर, प्रगति की निगरानी और सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देकर अंतर को पालते हैं। यह अनुरूप दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे और प्रत्येक छात्र अपनी गति से पढ़ने के कौशल को मजबूत कर सके।

ग्रामीण भारत में, साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से अधिक है, जो आजीवन सीखने और आजीविका की नींव प्रदान करती है। फिर भी, दशकों की प्रगति के बावजूद, अल्पविकसित समुदायों में बड़ी संख्या में बच्चे मूलभूत पढ़ने के कौशल के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं।

सही उम्र में धाराप्रवाह पढ़ने में असमर्थता न केवल अकादमिक प्रदर्शन को बाधित करती है, बल्कि जीवन में बाद में अवसरों के लिए दरवाजे भी बंद कर देती है, उच्च शिक्षा से लेकर सम्मानजनक रोजगार तक।

अकेले स्कूल इस अंतर को पाट नहीं सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कम-से-कम, एक एकल शिक्षक को विभिन्न पढ़ने के स्तर पर, 30-40 बच्चों के कई ग्रेड या कक्षाओं को संभालने के साथ काम किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव व्यक्तिगत ध्यान के लिए बहुत कम जगह छोड़ देता है। नतीजतन, कई बच्चों को बुनियादी साक्षरता में महारत हासिल किए बिना साल-दर-साल पदोन्नत किया जाता है, जिससे सीखने की कमी पैदा होती है जो केवल समय के साथ चौड़ी होती है।

एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जो समुदायों को जुटाता है, पुस्तकों तक पहुंच को मजबूत करता है, और जमीन से पढ़ने की संस्कृति का पोषण करता है।

यहां, जमीनी स्वयंसेवक एक अमूल्य भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय युवा, महिलाएं या सेवानिवृत्त शिक्षक अपने समुदायों के भीतर चैंपियन पढ़ने के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।

वे न केवल पढ़ने के सत्रों का नेतृत्व करते हैं और बच्चों को कहानियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान करते हैं जो कक्षाएं अक्सर नहीं कर सकती हैं। स्वयंसेवक अपने पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों को समूहीकृत करके, केंद्रित इनपुट देकर, प्रगति की निगरानी और सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देकर अंतर को पालते हैं। यह अनुरूप दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे और प्रत्येक छात्र अपनी गति से पढ़ने के कौशल को मजबूत कर सके।

जब बच्चे उन कहानियों के संपर्क में आते हैं जो उनकी वास्तविकताओं को दर्शाती हैं या उनकी कल्पना को चिंगारी देती हैं, तो पढ़ने का आनंद आत्मनिर्भर हो जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आसपास के गांवों के साक्ष्य, जो संभव है उसकी झलक प्रदान करते हैं। एक ग्रामीण रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और 2022-2024 के बीच मूल्यांकन किया गया था, ने सभी ग्रेड में पढ़ने में लगातार ऊपर की ओर रुझान का खुलासा किया, सामुदायिक स्वयंसेवकों को 'पुष्तक परियों' कहा जाता है।

प्रथम द्वारा वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (ASER) 2024 में इस कार्य की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है, जिससे पता चलता है कि प्रगति के बावजूद, ग्रामीण सीखने में लगातार अंतराल बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा III के सरकारी स्कूली बच्चों की कक्षा II-स्तरीय पाठ पढ़ने में सक्षम हिस्सेदारी 2022 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 23.4 प्रतिशत हो गई, ASER शुरू होने के बाद से उच्चतम स्तर।

कक्षा V के छात्रों में, पढ़ना प्रवाह एक ही अवधि में 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.8 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मूलभूत साक्षरता में सुधार हो रहा है, लेकिन बच्चों के बड़े वर्ग में अभी भी ग्रेड-स्तर के कौशल की कमी है, जो समुदाय-संचालित, स्वयंसेवक के नेतृत्व वाले पठन हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। पुस्तकों तक पहुंच एक और महत्वपूर्ण एनबलर है। उम्र-उपयुक्त और आकर्षक सामग्री के साथ स्टॉक किए गए छोटे, स्कूल या समुदाय-आधारित पुस्तकालय कक्षा के बाहर पढ़ने की आदत बनाने में मदद करते हैं।

जब बच्चे उन कहानियों के संपर्क में आते हैं जो उनकी वास्तविकताओं को दर्शाती हैं या उनकी कल्पना को चिंगारी देती हैं, तो पढ़ने का आनंद आत्मनिर्भर हो जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आसपास के गांवों के साक्ष्य, जो संभव है उसकी झलक प्रदान करते हैं। एक ग्रामीण रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और 2022-2024 के बीच मूल्यांकन किया गया था, ने सभी ग्रेड में पढ़ने में लगातार ऊपर की ओर रुझान का खुलासा किया, सामुदायिक स्वयंसेवकों को 'पुष्तक परियों' कहा जाता है।

दो कारक सबसे दृढ़ता से सुधार से जुड़े के रूप में उभरे: पढ़ने के सत्रों की संख्या में भाग लिया और पुस्तकों की संख्या पढ़ी। जो छात्र एक वर्ष से अधिक समय तक कार्यक्रम में रहे, उन्होंने न केवल तेजी से सुधार किया, बल्कि अपने साथियों की तुलना में उच्च पढ़ने के स्तर पर बाद के शैक्षणिक वर्षों की शुरुआत की, इस तथ्य का प्रदर्शन किया कि समुदाय समर्थित साक्षरता कार्यक्रम एक शानदार प्रभाव पैदा करते हैं। एक बार जब एक बच्चा पढ़ने में आत्मविश्वास बनाता है, तो अन्य विषयों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता में भी सुधार होता है।

ऐसे मॉडल साबित करते हैं कि परिवर्तन को महंगा नहीं होना चाहिए। निरंतर स्वयंसेवक भागीदारी, पुस्तकों तक स्थिर पहुंच और नियमित प्रोत्साहन के साथ, साक्षरता परिणामों में कम लागत पर नाटकीय रूप से सुधार किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की इस मॉडल को स्केल करने, प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ स्वयंसेवकों का समर्थन करने और निगरानी के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण साक्षरता केवल एक शिक्षा चुनौती नहीं है; यह एक विकास अनिवार्य है। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, वे स्कूल में रहने, उच्च अध्ययन करने, कौशल के अवसरों का उपयोग करने और सार्थक आजीविका को सुरक्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। समुदायों के लिए, साक्षरता ईंधन सशक्तिकरण, आवाज और एजेंसी को मजबूत करती है, और गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद करती है।

आगे का रास्ता स्पष्ट है: भारत को न केवल कक्षाओं और शिक्षकों में बल्कि स्वयं समुदायों की शक्ति में भी निवेश करना चाहिए। स्थानीय स्वयंसेवकों को पढ़ने के चैंपियन के रूप में उपयोग करके और पुस्तकों तक पहुंच के साथ पढ़ने की आदतों को एम्बेड करके, हम भारत के ग्रामीण बच्चों के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

जब शिक्षक छोड़ते हैं: द साइलेंट ग्लोबल एक्सोडस

विजय गर्ग

क्लासरूम अपने मशाल वाहक खो रहे हैं। जैसा कि शिक्षक विदेशी तटों के लिए अपना बैग पैक करते हैं, जो पीछे रह जाता है वह खाली डेस्क, संघर्षरत स्कूल और वायदा जोखिम में है। एक ऐसे युग में जब शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति के आधार के रूप में मनाया जाता है, प्रशिक्षित शिक्षकों का पलायन एक अस्थिर सवाल उठाता है: क्या हम वास्तव में उन लोगों का मूल्यांकन कर रहे हैं जो युवा दिमाग को आकार देते हैं, या क्या हम वैश्विक श्रम बाजारों को अपनी कक्षाओं के बहुत जीवनकाल को खत्म करने की अनुमति दे रहे हैं?

भारत की कहानी विशेष रूप से खुलासा कर रही है। हर साल, शिक्षकों की एक स्थिर धारा खाड़ी, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना होती है, जो वेतन और शर्तों से अधिक लालच देती है जो वे घर पर सामना करते हैं। केरल, अक्सर अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करता है, विरोधाभास को सबसे अधिक स्टारकली बनाता है। इसके प्रशिक्षित शिक्षकों का एक बड़ा अनुपात विदेशों में प्रवास करता है, जबकि राज्य के ग्रामीण और आदिवासी स्कूल रिक्तियों को भरने के लिए संघर्ष करते हैं। यह एक क्रूर विडंबना है: बहुत भूमि है कि अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के लिए शिक्षकों की आपूर्ति पूरी तरह से अपने कर्मचारियों को नहीं कर सकते। यह दुविधा भारत की अकेली नहीं है। अफ्रीका और कैरिबियन के पार, शिक्षा प्रणाली को अस्थिर किया जाता है क्योंकि शिक्षक एन मास को छोड़ देते हैं।

यहां तक कि ब्रिटेन, विडंबना यह है कि एक भर्ती और शिक्षक प्रवास का शिकार, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में हजारों शिक्षकों को खो देता है,

यहां तक कि यह जमैका और भारत से सक्रिय रूप से भर्ती करता है। इस तरह के वैश्विक परिसंचरण क्षण भर में एक राष्ट्र में कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन यह एक साथ दूसरे में संकटों को गहरा करता है, एक चक्र बनाता है जो उतना ही अस्थिर है जितना कि अन्यायपूर्ण है।

इस पलायन के चालक कोई रहस्य नहीं हैं। अपने गृह देशों में शिक्षक अल्प वेतन, खराब बुनियादी ढांचे, अत्यधिक कार्यभार और पेशेवर मान्यता की कमी से जूझ रहे हैं। विदेश में, उन्हें ठीक वही पेशकश की जाती है जो उन्हें घर पर अस्वीकार किया जाता है: स्थिरता, गरिमा और सम्मान। यह असंतुलन शिक्षकों को अपने स्वयं के समाजों के भीतर ज्ञान के अभिभावकों के बजाय वैश्विक बाजार में कारोबार करने वाली वस्तुओं में बदल देता है। बहस यह नहीं है कि क्या शिक्षक प्रवास एक चिंता का विषय है - यह निर्विवाद रूप से है - लेकिन हम इसका सामना करना कैसे चुनते हैं। कुछ आशावादी सुझाव देते हैं कि प्रवासन मस्तिष्क परिसंचरण को बढ़ावा दे सकता है, लौटने वाले शिक्षक वैश्विक अनुभव के साथ घरेलू प्रणालियों को समृद्ध करते हैं। फिर भी, अधिकांश विकासशील देशों के लिए, पैटर्न परिसंचरण नहीं है, बल्कि रक्तस्राव है - एक जो कक्षाओं को नालियों और असमानता को गहरा करता है।

भारत एक चौराहे पर खड़ा है। यूनेस्को का अनुमान है कि अगर देश को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है तो 2030 तक एक लाख से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि माइग्रेशन अनियंत्रित रहता है, तो यह दृष्टि मृगतृष्णा बनी रहेगी। समाधान विदेश में दरवाजे बंद करने में नहीं, बल्कि घर पर शिक्षण पेशे को बढ़ाने में निहित है: उचित वेतन, वास्तविक कैरियर की प्रगति, सहायक नीतियों को सुनिश्चित करना, और सबसे ऊपर, सांस्कृतिक श्रद्धा को बहाल करना, जिसने एक बार गुरु को बाकी सभी से ऊपर रखा था।

शिक्षक प्रवास केवल आंकड़ों या स्टाफिंग के बारे में नहीं है; यह मूल्यों के बारे में है। यह दर्शाता है कि समाज अगली पीढ़ी को आकार देने के लिए सौंपे गए लोगों को कैसे देखते हैं। जब एक शिक्षक प्रवास करता है, तो यह न केवल एक पेशेवर खो जाता है - यह एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। जब तक राष्ट्र अपने शिक्षकों को प्रगति के वास्तुकारों के रूप में सम्मानित करना नहीं सीखेंगे, वे शिक्षकों को निर्यात करना और गिरावट का आयात करना जारी रखेंगे।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

पुस्तक मेलों में अब पहले जैसे भीड़ उमड़ती नहीं दिखती

विजय गर्ग

जीवन में परिवर्तन अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन का तात्पर्य यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति को ही दरकिनार कर दें। कुछ ऐसा ही हमारा पुस्तकों के प्रति लगाव को देखा जा रहा है। खासकर युवा पीढ़ी और पुस्तक संस्कृति के बीच दूरियां काफी चिंता का विषय बन गई है। आज के युवाओं के बीच पुस्तकों के प्रति लगाव कम होने का मुख्य कारण डिजिटल दुनिया है, जहां स्मार्टफोन या मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक क्लिक के साथ किसी को हर तरह की सामग्री मिल जाती है। मगर सब कुछ व्यापक उपलब्धता के बीच पुस्तकों की जगह दिनों-दिन सिकुड़ती जा रही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पुस्तकों से युवा पीढ़ी का जुड़ाव कम होना न केवल युवा पीढ़ी के ज्ञान और रचनात्मकता को प्रभावित करती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और

साहित्य के संरक्षण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। समय रहते इस विषय पर गौर करना बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल मीडिया हमारे लिए बेहद अहम बनता जा रहा है, लेकिन किताबों से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। एक पुस्तक हमारे दिमाग के विकास के लिए बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं, तो इससे हमारे दिमाग में एकाग्रता का विकास होता है और इसके साथ ही हमारे ज्ञान की गहराई में इजाफा होता है।

आज की दौड़ती भागती जिंदगी में युवा पीढ़ी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह अपने इतिहास और विचार-गहनता की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए उन पर गहन अध्ययन को प्राथमिक और जरूरी माने।

पुस्तक मेलों की चमक यह बेवजह नहीं है कि पुस्तक मेलों में अब पहले जैसे भीड़ उमड़ती नहीं दिखती है। एक समय था, जब युवा पीढ़ी को इंतजार रहता था कि कब पुस्तक मेला लगे और वे अपनी पसंद की किताबें खरीद कर लाएं। अब तक किताबें ही मार्गदर्शन के साथ हमारा समय बिताने की साथी रही थीं। आज का युवा किताबों को ई-बुक पर पढ़ना चाहता है, ताकि आधुनिक होने का अहसास हो। मगर क्या हमें लगता है कि किताब को बिना स्पर्श किए वह अनुभूति हो सकती है जो हाथ में किताब लेकर पढ़ने में मिलती है?

दरअसल, किताब वह अहसास है जो जानकारियों और जिज्ञासाओं से बांधे रखता है। आज युवाओं के बीच नकारात्मकता इस कदर घर करती जा रही है कि इसकी वजह से ध्यान सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही। किताबें हम अक्सर उस समय पढ़ते हैं, जब हमें महसूस होता है कि खाली समय है या फिर अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में किताबें किसी दोस्त की तरह काम करती हैं। उनको पढ़कर एक अलग-सी शांति मिलती है। जहां हम तनाव महसूस करते हैं, वहां किताबें हमारे अंदर से तनाव को निकालकर दिमाग में सकारात्मकता और जीवन जीने की इच्छा को भर देती हैं। एक समय था जब किसी जगह पुस्तकालय मिल जाता था तो एक उत्सुकता होती थी वहां बैठ कर किताबे पढ़ने की पुस्तकालयों में पुस्तकों का इतना अधिक संग्रह होता था कि हमारे अंदर उन्हें पढ़ने की भी अलग-सी ललक होती थी। वहां हमें अपनी संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई देती थी। मगर आज युवा पीढ़ी के किताबों के प्रति अनदेखी करने वाले रवैए ने पुस्तकालयों को जैसे विलुप्त ही कर दिया है। आज के युवा इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे किताबों के लिए पुस्तकालय जैसी जगह पर जाएं।

बढ़ती होड़

मुश्किल यह है कि आज युवा पीढ़ी में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई है, जो उन्हें दिन-रात चैन से जीने नहीं देती है। खासकर माता-पिता की इच्छाएं युवाओं पर एक बोझ की तरह काम करने लगी हैं। उन्हें भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए शिक्षा में 'सबसे अव्वल' आने को अपना लक्ष्य बनाना है। इस क्रम में सिर पर पढ़ाई इस कदर हावी हो रही है कि युवाओं के पास समय की बेहद कमी होती जा रही है और वे अपने पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान और सृजनात्मक साहित्य की पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। जीवन में जो पुस्तकें हमें असल में वास्तविकता को दिखाती हैं, अगर उन्हें खरीदा भी जाता है तो अलमारी में सजा कर रखने के लिए।

यह एक विचित्र विडंबना है कि डिजिटल मंचों पर किसी भी चीज को खोज कर हमें विश्वास हो जाता है कि वह सही ही होगी, लेकिन इसके विपरित एक किताब को हम नहीं पढ़ना चाहते, जिसे किसी लेखक ने अपने अनुभवों से सींचा होगा, बड़ी मेहनत से लिखा होगा और उसमें वास्तविकता दर्ज होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि हम गूगल में खोज कर जो चीजें हासिल करते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी होती है? हम इस ओर ज्यादा गौर नहीं करते है, क्योंकि हमें सिर्फ पकी पकाई सामग्री चाहिए होती है। यहां युवाओं को समझना होगा कि अगर उन्हें ज्ञान से लैस जागरूक नागरिक बनना है, तो जरूरी है कि वे पुस्तकों से दूरी न बनाएं। उनमें विषयों को खोजें। जो गुणवत्ता से लैस जानकारी पुस्तकों में मिलेगी, उसकी तुलना डिजिटल मंचों पर बिखरी हुई सामग्री में नहीं मिलेगी।

बुद्धिमत्ता का विकास

किताबें नियमित रूप से पढ़ने से याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इससे तनाव से मुक्ति और स्फूर्ति भी मिलती है। अगर किताबों को ध्यान से पढ़ा जाए तो विषय की गहरी समझ पैदा होती है। साथ ही किताबें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति विकसित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान, कल्पना और रचनात्मकता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। वे हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के बारे में जानने में मदद करती हैं और हमें दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती हैं। जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव को हम किताबों के जरिए भी जान पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अगर हम रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हैं तो हमें बेहद सुकून भरी नींद आती है। पूरे दिन में पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है तो रात को सोते समय मोबाइल पर वक्त बिताने से अच्छा है कोई किताब पढ़ी जाए। जिस दिन हमने पुस्तक को अपनी धरोहर की तरह संभाल कर उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो जीवन के सारे अवसाद स्वयं ही खत्म होते दिखेंगे। अच्छी नींद के साथ सुबह मन खुशनुमा महसूस करेगा।

भारत वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है

विजय गर्ग

भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव से गुजर रहा है, एक युवा आबादी से एक उम्र बढ़ने के लिए संक्रमण। यह परिवर्तन प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के संयोजन से प्रेरित है। हालांकि यह स्वास्थ्य सेवा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार का प्रतिबिंब है, यह देश की अर्थव्यवस्था, समाज और सार्वजनिक नीति के लिए जटिल चुनौतियों और अवसरों का एक सेट भी प्रस्तुत करता है। भारत की एजिंग जनसंख्या के प्रमुख ड्राइवर प्रजनन दर में गिरावट: भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर), एक महिला के जीवनकाल में औसतन बच्चों की संख्या, कई क्षेत्रों में 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। इसका मतलब यह है कि औसतन, एक महिला के पास खुद को और अपने साथी को बदलने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हैं, जिससे युवा लोगों का सिकुड़ता आधार बन जाता है।

बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा: स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण में प्रगति के कारण, भारतीय लंबे समय तक रह रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में जीवन प्रत्याशा में काफी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धावस्था में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा है।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: बढ़ी हुई महिला शिक्षा और कार्यबल की भागीदारी जैसे कारक अक्सर शादी और बच्चे के जन्म में देरी के साथ सहसंबंधित होते हैं, प्रजनन दर में गिरावट में और योगदान देते हैं। एक उम्र बढ़ने की आबादी का प्रभाव इस जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूरगामी परिणाम हैं:

आर्थिक निहितार्थ:

सिकुड़ते कार्यबल: कामकाजी आयु के व्यक्तियों के एक छोटे अनुपात को बढ़ती बुजुर्ग आबादी का समर्थन करना होगा, जिससे उच्च निर्भरता अनुपात होगा। इसके परिणामस्वरूप कर का एक छोटा आधार और श्रम की कमी हो सकती है।

राजकोषीय दबाव में वृद्धि: बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह सार्वजनिक वित्त को तनाव दे सकता है और नीति समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

कम आर्थिक विकास के लिए संभावित: एक उम्र बढ़ने कार्यबल उत्पादकता को कम कर सकता है और प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं होने पर धीमी आर्थिक वृद्धि हो सकती है।

सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:

हेल्थकेयर सिस्टम पर तनाव: बुजुर्गों में पुरानी बीमारियों की व्यापकता अधिक होती है, जिससे जराचिकित्सा देखभाल, दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं और विशेष चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती मांग होती है।

पारंपरिक परिवार के समर्थन का क्षरण: शहरीकरण, प्रवास और परमाणु परिवारों के उदय के कारण बुजुर्गों की देखभाल करने वाले संयुक्त परिवार की पारंपरिक प्रणाली कमजोर हो रही है। यह कई पुराने लोगों को वित्तीय और सामाजिक असुरक्षा की चपेट में ले जाता है।

बुजुर्गों की भेद्यता: भारत की बुजुर्ग आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, पर्याप्त आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव

है। यह उन्हें गरीबी और वित्तीय कठिनाई के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। सरकारी पहल और नीति प्रतिक्रियाएँ इस जनसांख्यिकीय बदलाव को पहचानते हुए, भारत सरकार ने बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं:

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना।

अटल पेंशन योजना ( ): एक पेंशन योजना जो ग्राहकों को एक गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ( ): गरीबी रेखा से नीचे ( ) परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करता है।

हेल्थकेयर और वित्तीय सहायता:

आयुष्मान भारत: स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसमें बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: वरिष्ठ नागरिकों के निवेश के लिए एक निश्चित और उच्च ब्याज दर प्रदान करता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम ( ): वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और मोबाइल मेडिकल इकाइयों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

कानूनी और सामाजिक ढांचे:

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 का रखरखाव और कल्याण: यह अधिनियम बच्चों के लिए अपने माता-पिता को बनाए रखने के लिए एक कानूनी दायित्व बनाता है और इसे लागू करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति: पुराने व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ₹एजिंग इन प्लेस,₹ आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं की अवधारणा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। एक नज़र आगे भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण अपरिहार्य है। जबकि एक बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी का ₹जनसांख्यिकीय लाभांश₹ अभी भी एक वास्तविकता है, अवसर की खिड़की बंद हो रही है। चुनौतियों को कम करने और इस जनसांख्यिकीय बदलाव की क्षमता का दोहन करने के लिए, भारत को इसकी आवश्यकता है:

स्किलिंग एंड प्रोडक्टिविटी में निवेश करें: महिलाओं सहित मौजूदा कार्यबल के कौशल और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे सकें।

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करें: पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की कवरेज और पर्याप्तता का विस्तार करें, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए।

सुधार हेल्थकेयर: एक मजबूत फोकस के साथ एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण करें

सक्रिय एजिंग को बढ़ावा दें: लचीले काम के विकल्पों और आजीवन सीखने के माध्यम से पुराने लोगों को कार्यबल और समाज में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करें और सक्षम करें। संक्षेप में, उम्र बढ़ने की आबादी की दिशा में भारत का कदम सक्रिय और व्यापक नीति नियोजन का आह्वान है जो आर्थिक जीवन शक्ति को बनाए रखते हुए अपने बढ़ते वरिष्ठ नागरिक समुदाय की भलाई और गरिमा सुनिश्चित करता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

हिंदी भविष्य में रोजगार के नए रास्ते खोलेगी

-संदीप सृजन

हिंदी, भारत की राजभाषा और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है बल्कि यह आधुनिक युग में रोजगार के नए द्वार खोलने की क्षमता रखती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ बाईस आधिकारिक भाषाएँ हैं, हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में उभर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग साठ करोड़ से अधिक है, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली माध्यम बनाती है। लेकिन क्या हिंदी केवल साहित्य और संवाद तक सीमित है? बिल्कुल नहीं! भविष्य में यह डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, मीडिया, पर्यटन, अनुवाद और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान करेगी। आज के दौर में, जब वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति तेजी से हो रही है, हिंदी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। नई शिक्षा नीति में हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है, जो युवाओं के लिए नई संभावनाएँ पैदा कर रही है।

वर्तमान में हिंदी से जुड़े रोजगार मुख्य रूप से शिक्षा, सरकारी नौकरियों, पत्रकारिता और प्रकाशन तक सीमित हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र में हिंदी अधिकारी, अनुवादक और शिक्षक के पद उपलब्ध हैं। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी के माध्यम से दस्तावेजीकरण और संचार का कार्य होता है। राजभाषा विभाग के अनुसार, भारत में लगभग दस लाख से अधिक लोग हिंदी से संबंधित नौकरियों में कार्यरत हैं।शिक्षा क्षेत्र में हिंदी स्नातक करने वाले युवाओं को स्कूलों और महाविद्यालयों में अध्यापक बनने का अवसर मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदी विभागों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पत्रकारिता में हिंदी समाचार चैनल और डिजिटल मंचों पर रिपोर्टर, एंकर और संपादक के पद उपलब्ध हैं।

प्रकाशन उद्योग में हिंदी पुस्तकों, पत्रिकाओं और ई-पुस्तकों की मांग बढ़ रही है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे मंचों पर हिंदी सामग्री की बिक्री में बीस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। आज के डिजिटल युग में हिंदी कॉन्टेंट की मांग अंग्रेजी से पाँच गुना तेज़ी से बढ़ रही है। इस प्रकार, वर्तमान में हिंदी रोजगार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में यह और विस्तृत होगा। भविष्य का रोजगार डिजिटल दुनिया पर निर्भर है, और यहाँ हिंदी की भूमिका अहम है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की खपत तेजी से बढ़ रही है। गूगल के अनुसार, भारत में पचास प्रतिशत से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हिंदी में खोज करते हैं। इससे डिजिटल विपणन, सामग्री निर्माण और सामाजिक मीडिया प्रबंधन में हिंदी विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। डिजिटल सामग्री निर्माता के रूप में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हिंदी वीडियो बनाना एक लाभकारी करियर है। दो हजार पच्चीस के अंत तक, भारत में अस्सी करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, जिनमें से अधिकांश हिंदी माध्यम पसंद करेंगे।

सोशल मीडिया ने हिंदी को नई ऊर्जा दी है और वैश्विक मंचों तक पहुँचाने का माध्यम बना है। उदाहरणस्वरूप, हिंदी पॉडकास्ट और ब्लॉगिंग से लाखों कमाई हो रही है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता- आधारित उपकरणों के साथ हिंदी सामग्री निर्माण के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।ई-शिक्षण मंचों पर हिंदी पाठ्यक्रम की मांग बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत, हिंदी माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शिक्षकों और सामग्री विकासकर्ताओं के लिए नौकरियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हिंदी इंटरफेस विकसित कर रही हैं, जैसे गूगल अनुवाद का हिंदी संस्करण। इससे सॉफ्टवेयर विकासकर्ता जो हिंदी में कोडिंग समझ सकें, के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन क्षेत्र में हिंदी गाइड और यात्रा ब्लॉगर के रूप में रोजगार बढ़ेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए हिंदी-अंग्रेजी मिश्रित यात्रा पैकेज लोकप्रिय हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दो हजार तीस तक भारत में पर्यटन उद्योग दस प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद योगदान देगा, जिसमें हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

शिक्षा हमेशा से हिंदी का मजबूत क्षेत्र रहा है, लेकिन भविष्य में यह और विस्तृत होगा। नई शिक्षा नीति में तीन भाषा सूत्र के तहत हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की मांग बढ़ेगी। देश भर में हाल ही में जारी विज्ञप्तियों में हिंदी के लिए सैकड़ों पद घोषित हुए हैं। भविष्य में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पढ़ाने के अवसर बढ़ेंगे। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ शिक्षकों की वेतन पचास हजार डॉलर प्रति वर्ष तक है। ऑनलाइन मंचों पर हिंदी शिक्षकों के लिए स्वतंत्र कार्य का बाजार खुल रहा है।

अनुवाद क्षेत्र में हिंदी का महत्व और अधिक होगा। वैश्विक व्यापार में, कंपनियाँ हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता महसूस कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गज कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुवाद उपकरण विकसित कर रहे हैं, लेकिन मानवीय अनुवाद की मांग बनी रहेगी। हिंदी कॉन्टेंट की मांग अंग्रेजी से पाँच गुना तेज़ी से बढ़ रही है। दो हजार तीस तक, अनुवाद उद्योग का बाजार पचास अरब डॉलर का हो जाएगा, जिसमें हिंदी का बड़ा हिस्सा होगा। स्वतंत्र मंचों जैसे अपवर्क पर हिंदी अनुवादकों को प्रति परियोजना पाँच सौ से दो हजार डॉलर मिलते हैं। इसके अलावा, साहित्यिक अनुवाद से लेखकों को नई पहचान मिलेगी। हिंदी उपन्यासों का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद वैश्विक बाजार खोलेगा। मीडिया उद्योग हिंदी के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। हिंदी फिल्में, वेब श्रृंखलाएँ और ओवर द टॉप मंचों पर हिंदी सामग्री की मांग तीस प्रतिशत सालाना बढ़ रही है। पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्माता के पद उपलब्ध होंगे। मनोरंजन में, खेल विकास उद्योग हिंदी समर्थन जोड़ रहा है। मोबाइल खेलों में हिंदी वर्णन से विकासकर्ताओं को नौकरियाँ मिलेंगी।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में, व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और ग्राहक सेवा में हिंदी एजेंटों की मांग बढ़ेगी। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-वाणिज्य मंचों पर हिंदी ग्राहक सहायता टीम हैं। भविष्य में, हिंदी विपणन रणनीतिकार ग्रामीण भारत को लक्ष्य करेंगे, जहाँ सत्तर प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती है। हिंदी बाजार की भाषा बन गई है, खरीद-बिक्री की भाषा बन गई है, लेकिन अभी पूंजी निर्माण की भाषा नहीं बन पाई है। लेकिन प्रवृत्तियों से पता चलता है कि यह पूंजी निर्माण की भाषा बनेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, हिंदी भारत-रूस, भारत-जापान जैसे संबंधों को मजबूत करेगी। हिंदी जानने वाले राजनयिकों और व्यापार विश्लेषकों की जरूरत पड़ेगी।

हालाँकि हिंदी के प्रसार में चुनौतियाँ भी हैं। अंग्रेजी का वर्चस्व एक बड़ी बाधा है। आज वैश्विक मान्यता है कि अंग्रेज़ी जानने से रोज़गार के साथ-साथ तकनीक व विज्ञान के अनगिनत दरवाज़े खुलते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी के लोग अन्य भाषाएँ सीखने से हिचकते हैं जबकि गैर-हिंदी क्षेत्र हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। डिजिटल विभाजन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी सामग्री की पहुँच कम है। समाधान के रूप में, हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। सरकार को हिंदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित करने के लिए निवेश करना चाहिए। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों में हिंदी को शामिल करना होगा।

परमाणु शक्ति: विकास की आड़ में मृत्यु का सौदा....

[परमाणु कचरा: चमकती रोशनी के पीछे का अंधकार]

एक कड़वा सच हमें हर पल झकझोरता है जब हम "स्वच्छ ऊर्जा" के नाम पर परमाणु शक्ति का गुणगान करते हैं, तो उस भयावह छाया को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी धरती और भावी पीढ़ियों पर सदियों तक मंडराएगी: न्यूक्लियर कचरा। यह कचरा कोई सामान्य कूड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा घातक ज़हर है जो लाखों वर्षों तक हमारे ग्रह को विषाक्त करता रहेगा। हमारी सभ्यता की चकाचौंध के पीछे छिपा यह डरावना सच केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक गहन नैतिक और अस्तित्वगत संकट है। परमाणु ऊर्जा को जलवायु परिवर्तन का रामबाण बताकर हम आज की समस्याओं को भले ही टाल लें, मगर इसके विनाशकारी परिणामों की भारी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएँगी। यह एक ऐसी विरासत है, जिसे कोई भी संतान स्वीकार नहीं करना चाहेगी।

परमाणु ऊर्जा को "हरित" और "स्वच्छ" का तमगा देकर आसमान पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काबू में रखता है। विश्व ऊर्जा परिषद के मुताबिक, यह वैश्विक बिजली का 10% हिस्सा देती है और 2023 तक 2.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने में मददगार रही। लेकिन इस चमकदार आँकड़े की आड़ में एक भयावह सच छिपा है: उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा, एक ऐसा ज़हर जो धरती को लाखों वर्षों तक दूषित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) बताती है कि हर साल 10,000 टन यह घातक कचरा पैदा होता है, जिसमें यूरेनियम-238 और प्लूटोनियम-239 जैसे तत्व 10,000 से 24,000 वर्षों तक रेडियोधर्मी रहते हैं। इतने लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखना मानव सभ्यता के लिए एक असंभव-सी चुनौती है।

इस कचरे का प्रबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं। आज अधिकांश देश इसे अस्थायी भंडारण में डालकर टालमटोल करते हैं—पानी के पूल या स्टील-कंक्रीट के कंटेनरों में। मिसाल के तौर पर, अमेरिका की हनफोर्ड साइट पर 56 मिलियन गैलन रेडियोधर्मी कचरा 177 भूमिगत टैंकों मेंजमा है, जिसके लिए अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं है। फिनलैंड की ओनकॉलो परियोजना, जो 2025 में शुरू होगी, गहरे भूगर्भीय भंडारण की दिशा में एकमात्र गंभीर कदम है। मगर सवाल अनुत्तरित है—क्या हम भूकंप, भू-स्खलन या मानवीय भूलों से लाखों वर्षों तक इस कचरे को सुरक्षित रख पाएँगे? इतिहास चीख-चीखकर बताता है कि मानव सभ्यताएँ कुछ हजार वर्षों में ही धूल में मिल जाती हैं। फिर, लाखों वर्षों की गारंटी कौन देगा?

इसका एक और डरावना पहलू है—सुरक्षा का संकट। यह कचरा केवल प्राकृतिक आपदाओं का शिकार नहीं, बल्कि मानव निर्मित खतरों का भी आसान निशाना है। 2011 का फुकुशिमा हादसा इसकी मिसाल है, जहाँ प्रकृति ने मानव की लापरवाही को बेनकाब किया। लेकिन अगर आतंकवादी इस कचरे को हथियार बना लें तो? आईएईए की रिपोर्ट बताती है कि 2001 से 2020 तक रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी या दुरुपयोग की 3,000 से ज्यादा घटनाएँ हुई हैं। प्लूटोनियम की मामूली मात्रा से बनने वाला ₹डर्टी बम₹ लाखों जिंदगियों को तबाह कर सकता है। यह खतरा सिर्फ़ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं से भी भरा है।

न्यूक्लियर कचरे का कहर सिर्फ़ पर्यावरण तक नहीं रुकता; यह मानवता के स्वास्थ्य पर सदियों तक छाया रहता है। रेडियोधर्मी कण कैंसर, आनुवंशिक विकृतियाँ और जन्मजात रोगों का जाल बुनते हैं। 1986 के चेर्नोबिल हादसे ने इसका भयावह चेहरा दिखाया—यूक्रेन और बेलारूस में थायरॉइड कैंसर के मामले 10 गुना बढ़ गए, और यह अभिशाप पीढ़ियों तक गूँज रहा है। अगर न्यूक्लियर कचरे का रिसाव हुआ, तो यह पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला को ज़हरीला बना देगा, जिसका दंश सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। क्या हमारी अल्पकालिक सुविधा के लिए इतना भयंकर जोखिम उचित है?

इसके समाधान के लिए साहसिक और बहुआयामी कदम जरूरी हैं। सबसे पहले, परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता घटानी होगी। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों ने पिछले दशक में क्रांति ला दी है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुसार, 2023 तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता 1,000 गीगावाट को पार कर चुकी है। ये स्रोत न सिर्फ़ सुरक्षित हैं, बल्कि इनका कोई ज़हरीला कचरा भी नहीं। दूसरा, न्यूक्लियर कचरे के निपटान के लिए नवाचार अनिवार्य है। ₹ट्रांसम्यूटेशन₹ जैसी तकनीक, जो रेडियोधर्मी तत्वों को कम खतरनाक बनाती है, पर शोध को गति देनी होगी। मगर सबसे बड़ा बदलाव हमारी सोच में चाहिए। हमें यह मानना होगा कि ₹असीमित विकास₹ का भ्रम टिकाऊ नहीं। यह वक्त है कि हम भविष्य की खातिर आज अपनी प्राथमिकताएँ बदलें।

न्यूक्लियर कचरे के इस संकट से निपटने के लिए हमें साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, परमाणु ऊर्जा पर हमारी निर्भरता को तत्काल कम करना होगा। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों ने बीते दशक में चमत्कारिक प्रगति की है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुसार, 2023 तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता 1,000 गीगावाट को पार कर चुकी है। ये स्रोत न सिर्फ़ सुरक्षित हैं, बल्कि इनका कोई ज़हरीला अवशेष भी नहीं छोड़ता। दूसरा, न्यूक्लियर कचरे के निपटान के लिए क्रांतिकारी नवाचार अनिवार्य हैं। ₹ट्रांसम्यूटेशन₹ जैसी तकनीक, जो रेडियोधर्मी तत्वों को कम खतरनाक बनाती है, पर शोध को और तेज करना होगा। मगर इन सबसे ऊपर, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ₹असीमित विकास₹ का भ्रम अब टिकाऊ नहीं, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें गले लगाना होगा।

एक अनदेखा सवाल सांस्कृतिक स्मृति का है: अगर हम आज न्यूक्लियर कचरे को भूमिगत दफन कर दें, तो क्या लाखों वर्ष बाद कोई सभ्यता इसे समझ पाएगी? प्राचीन मिस्र के पिरामिड, जो मात्र 5,000 वर्ष पुराने हैं, आज भी रहस्यमय हैं। लाखों वर्ष बाद हमारे बनाए चेतावनी चिन्ह—शिलालेख हों या प्रतीक—क्या कोई अर्थ रखेंगे? नासा और वैज्ञानिक समूह इस दिशा में अनूठे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ₹रे-कैट सॉल्यूशन₹, जिसमें जीन-इंजीनियरिंग से ऐसी बिल्लियाँ बनाई जाएँ जो रेडिएशन के संपर्क में रंग बदलें। यह विचार भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन यह दर्शाता है कि हम इस संकट की गंभीरता को कितनी शिद्दत से समझ रहे हैं।

न्यूक्लियर कचरा सिर्फ़ विज्ञान की समस्या नहीं, बल्कि मानवता का संकट है। यह एक चेतावनी है कि हमारी तकनीकी उड़ान हमारी नैतिक समझ से कहीं आगे निकल चुकी है। परमाणु ऊर्जा को ₹स्वच्छ₹ कहना एक आधा सच है, क्योंकि इसका कचरा न सिर्फ़ प्रकृति को, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों को खोखला करता है। हमें उन ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देनी होगी जो न केवल आज, बल्कि लाखों वर्ष बाद भी धरती को सुरक्षित रखें। यह समय है कि हम अपनी लालसा पर लगाम लगाएँ, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और एक ऐसी दुनिया रचें जो न सिर्फ़ हमारे लिए, बल्कि अनगिनत भावी पीढ़ियों के लिए भी जीवंत और सुरक्षित हो। न्यूक्लियर कचरा हमें चेताता है— हर चमक के पीछे एक गहरी छाया है, और यह छाया हमारे भविष्य को निगलने को तैयार है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

क्या आने वाले समय में भारत 'युवा राष्ट्र' नहीं रह पायेगा!

रामस्वरूप रावतसरे

आज दुनिया एक बेहद महत्वपूर्ण जनसंख्या मोड़ पर खड़ी है। एक ओर कुछ देशों में अब भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर कई देश गंभीर गिरावट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 'विश्व जनसंख्या संभावना 2024' रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दशकों में वैश्विक आबादी का विकास पहले के अनुमान से धीमा रहेगा।

2030 के बाद दुनिया की जनसंख्या लगभग 10.2 अरब तक पहुँचेगी जो पिछले अनुमानों से करीब 70 करोड़ कम है। इसका मतलब है कि जन्म दर लगातार घट रही है और बहुत से देशों में लोग अब परिवार छोटा रखने लगे हैं। इस बदलाव के असर गहरे हैं। जब किसी देश में जन्म दर गिरती है और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेंशन और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है।

ऐसे में सरकारों को अधिक वृद्ध लोगों की देखभाल करनी पड़ती है लेकिन कार्यबल यानी काम करने वाले युवाओं की संख्या घटने लगती है। यही वजह है कि आज जनसंख्या का यह बदलाव केवल जनसंख्या विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी बन गया है।

भारत लंबे समय तक 'युवा राष्ट्र' कहलाता रहा है। यह वह देश है जहाँ कामकाजी उम्र की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती थी लेकिन अब आँकड़े बदलती तस्वीर दिखा रहे हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली(एसआरएस) 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1971 में 5.2 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी कम है। इसके साथ ही 0-14 साल की आयु वर्ग की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। 1991 में यह 36 प्रतिशत से ज्यादा थी जो अब 24 प्रतिशत पर आ गई है यानी नए बच्चों की संख्या कम हो रही है। दूसरी तरफ कामकाजी उम्र (15-59 साल) वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 66 प्रतिशत हो चुकी है। यह फिलहाल भारत की आर्थिक ताकत है, लेकिन आने वाले समय में यही समूह धीरे-धीरे वृद्ध होता जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 60 साल और उससे ऊपर की आबादी अब लगभग 10 प्रतिशत हो चुकी है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 14-15 प्रतिशत तक पहुँच गई है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और जन्म दर में गिरावट सकारात्मक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आने वाले वर्षों में भारत का युवा आधार सिकुड़ सकता है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या और जनसांख्यिकीय बदलाव पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि हर भारतीय दंपत्ति को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार जिन समुदायों की जन्म दर तीन से कम होती है, वे धीरे-धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार में तीन बच्चों को शामिल करना जरूरी है। भागवत ने कहा कि डॉक्टरों ने भी उन्हें बताया है कि सही उम्र में शादी करना और तीन बच्चे पैदा करना माता-पिता और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उनके अनुसार तीन भाई-बहनों वाले घरों में बच्चे आपस में सामंजस्य, अहंकार प्रबंधन और रिश्तों को संभालने की कला सीखते हैं, जिससे उनके भविष्य के पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की जनसंख्या नीति प्रतिस्थापन स्तर पर 2.1 बच्चों की सिफारिश करती है, लेकिन वास्तविक जीवन में 0.1 बच्चा होना संभव नहीं है। इसलिए गणना के हिसाब से दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा होना चाहिए।

भागवत का कहना था कि जनसंख्या को नियंत्रित और पर्याप्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक परिवार को तीन बच्चों का लक्ष्य रखना चाहिए लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तभी बच्चों की परवरिश और शिक्षा सही ढंग से हो पाएगी। जनसांख्यिकी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी समुदायों में जन्म दर घट रही है और यह बदलाव हिंदुओं में अधिक नजर आता है क्योंकि उनकी जन्म दर शुरू से ही कम रही है। भागवत ने धर्मांतरण और घुसपैठ को भी जनसंख्या असंतुलन का कारण बताया।

जनसंख्या असंतुलन भारत अकेला नहीं है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई देश इस चुनौती से जूझ रहे हैं। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2008 के बाद से वहाँ की जनसंख्या लगातार घट रही है। शादी और बच्चों के प्रति रुझान कम हो चुका है और अब वहाँ बुजुर्गों की संख्या युवाओं से कहीं अधिक हो गई है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया में जन्म दर दुनिया की सबसे कम है, जिसके कारण सरकार को कई सामाजिक और आर्थिक संकट झेलने पड़ रहे हैं। यूरोप भी इस संकट का सामना कर रहा है। ग्रीस में जन्म दर इतनी घट गई है कि वहाँ 5 प्रतिशत स्कूल बंद करने पड़े। बुल्गारिया, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों में 2050 तक जनसंख्या में 20 प्रतिशत से अधिक गिरावट आने की आशंका है। इटली और जर्मनी जैसे देशों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है।

टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क का मानना है कि 'कम जन्म दर मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।' मस्क खुद 13 बच्चों के पिता हैं और 'अधिक बच्चे पैदा करने' की सोच का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि अगर हर परिवार तीन बच्चे पैदा करे, तो जनसंख्या स्थिर रह सकती है। वे बार-बार चेतावनी देते हैं कि अगर जन्म दर घटती रही, तो 'पश्चिम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।' मस्क 'जनसंख्या विस्फोट' की चिंता को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यह एक 'भ्रांत धारणा' है और असली खतरा 'जनसंख्या गिरावट' है। उन्होंने यह भी कहा है कि वास्तव में प्रतिस्थापन दर 2.1 नहीं बल्कि लगभग 2.7 होनी चाहिए क्योंकि कुछ परिवार बच्चे नहीं पैदा करते।

विशेषज्ञों का मानना है कि मस्क की बातों में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति भी हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है और यह 2100 तक चरम पर पहुँचेगी। गति धीमी हो रही है और कई देशों में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। कुछ अध्ययनों का तो कहना है कि आबादी घटने के बावजूद अगर शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य में निवेश बढ़े तो समाज का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।

घटती जनसंख्या और बढ़ती वृद्धावस्था आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और रूस में इसके प्रभाव पहले से दिख रहे हैं। अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी इसका असर धीरे-धीरे महसूस किया जाने लगा है।

जानकारों के अनुसार भारत को अपनी युवा आबादी के वर्तमान लाभ का पूरा उपयोग करना होगा और साथ ही भविष्य की तैयारी करनी होगी। यदि अभी से परिवार-अनुकूल नीतियाँ, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दशकों में भारत भी वही स्थिति झेलेगा जो आज जापान या यूरोप झेल रहे हैं।

नेपाल में क्या और क्यों हो रहा है : राजेश कुमार पासी

पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल ने एक क्रांति हो रही है। कहने को यह क्रांति है लेकिन यह जनता का गुस्सा है जो छात्रों के माध्यम से सड़कों पर उतर आया है। नेपाल में इस आंदोलन को जेन जी आंदोलन का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें ज्यादातर 18 से 30 साल तक के युवा शामिल हैं। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई पीछे से इसे संचालित कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किया गया आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। इसे सत्ता परिवर्तन करने वाला आंदोलन बताया जा रहा है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है।

देखा जाए तो अब ये आंदोलन अराजकता का रूप ले चुका है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया

प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद इस आंदोलन में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा भी जुड़ गया। आंदोलन के हिंसक होने का कारण पुलिस फायरिंग में 24 युवाओं की मौत होना है क्योंकि इसके बाद ही पूरे देश में हिंसा भड़क गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा होने के बाद भी युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर बैन हटा दिया गया तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और वो भी पूरी हो गई लेकिन आंदोलन फिर भी नहीं रुका। इसके विपरीत यह आंदोलन और भयानक रूप ले चुका है। भीड़ ने राष्ट्रपति निवास, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित कितने ही वर्तमान और पूर्व मंत्रियों के घर फूंक दिए हैं। प्रधानमंत्री ओली का निजी घर भी फूंक दिया गया है।

इसके अलावा बड़े-बड़े होटल जलाए जा रहे हैं और अन्य सरकारी भवनों को भी आग लगाई जा रही है। सेना सड़को पर उतर आई है और छात्रों से मीटिंग करने की बात कही जा रही है। नेपाल के डिप्टी पीएम व वित्त मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। पूर्व पीएम और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को उनके घर से निकालकर पीटा गया और उनकी पत्नी को भी बुरी तरह से पीटा गया है। नेपाली कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय को भी आग लगा दी गई है क्योंकि यह पार्टी ओली का समर्थन कर रही थी।

यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चलाया जा रहा है जबकि इसमें अपराधी तत्व शामिल हो गए हैं। वो इस आंदोलन की अराजकता का फायदा उठा रहे हैं जिसके कारण लगभग 13000 कैदी जेल से भाग गए हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर भी हमला किया गया है जबकि इस आंदोलन से मंदिर का कोई लेना-देना नहीं है। नेपाल गए हुए भारतीयों पर हमला किया जा रहा है जबकि भारतीयों का इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि इस आंदोलन को शुरू करने में किसी विदेशी ताकत का हाथ न रहा हो लेकिन अब जरूर इसमें विदेशी ताकते शामिल हो गई हैं।

नेपाल से दिल्ली आए युवक से कनॉट प्लेस में ट्रांसजेंडर्स ने की लूटपाट, दो लिए गए हिरासत में

दिल्ली के कनाट प्लेस में नेपाल से आए एक युवक से दो ट्रांसजेंडरों ने 2600 रुपये लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों सोना और मुस्कान को हिरासत में ले लिया और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

नई दिल्ली। नेपाल से आए एक युवक से कनॉट प्लेस इलाके में दो ट्रांसजेंडरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने युवक की मदद से दोनों ट्रांसजेंडरों को हिरासत में ले लिया, जिनकी पहचान सुभाष नगर की सोना और मुस्कान के रूप में हुई है। उनके पास से लूटे गए 2,600 नकद भी बरामद कर लिए गए हैं। उनसे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच की जा रही है।

खड़े थे मेट्रो स्टेशन के पास : पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 32 वर्षीय राजा राम चौधरी नेपाल के कंचनपुर के रहने वाले हैं। वह नौ सितंबर को नेपाल से दिल्ली में यूक्रेन एंबेसी आए थे। सुबह करीब 10 बजे वह अपने तीनों दोस्तों के साथ शिवाजी मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी दो ट्रांसजेंडर आए और पैसे मांगने लगे।

मांगने लगे बड़ी रकम की नेघ : उन्होंने दोनों को 100-100 रुपए दे दिया। उसके बाद दोनों उनसे 2,600 रुपये नेघ मांगने लगे। उन्होंने तब रुपये देने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों ने उनके दोस्तों के सामने ही जबरदस्ती मारपीट कर 2,600 रुपये लूट लिए।

उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने ट्रांसजेंडरों की तलाश शुरू की। दोनों कनॉट प्लेस इलाके में घूमते पाए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उनके पास से लूटी गई नकदी बरामद की गई।

घर का बना खाना खाएँ और स्वस्थ रहें: उपमुख्यमंत्री श्रीमती परीदा आदिवासी महिलाओं के स्वस्थ रहने का कारण है मंडिया

मनोरंजन सासमल, बिरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर : उपमुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परीदा ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ दिमाग भी ज़रूरी है। आज महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से भुवनेश्वर स्थित लेमनट्री प्रीमियम में ₹स्वस्थ आहार अभियान₹ का शुभारंभ किया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परीदा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और विभिन्न खान-पान की आदतों पर चर्चा की तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी महिलाओं के स्वस्थ शरीर का कारण मंडिया है। उन्होंने बाज़ार के जंक फ़ूड से दूर रहने और घर के खाने के साथ-साथ पारंपरिक भोजन जैसे मंडिया, पखाल और पीठा आदि अपनाने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से गाँव की महिलाओं में मोटापा कम करने पर ध्यान केंद्रित किया।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शुभा शर्मा, विभागीय निदेशक मोनिषा बनर्जी, प्रसिद्ध ओडिया फिल्म अभिनेता सब्यसाची मिश्रा, अभिनेत्री श्रीमती अर्चिता साहू और अभिनेत्री अनु चौधरी, पोषण विशेषज्ञ एवं यूनिसेफ के

वरिष्ठ अधिकारी श्री सौरभ भट्टाचार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के अधिकारी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शुभा शर्मा ने गाँव में आँगनवाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चों में चिप्स और नूडल्स खाने की आदत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों की खान-पान की आदतों में बदलाव लाने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पोषण विशेषज्ञ और यूनिसेफ अधिकारी सौरभ भट्टाचार्य ने फिट रहने के लिए घर के बने खाने और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाने पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराने और अन्नप्राशन के बाद भी बच्चे को तैलीय भोजन से दूर रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने मोबाइल फोन से दूर रहकर स्क्रीन टाइम कम करने पर ज़ोर दिया।

इस कार्यक्रम में पोषण विशेषज्ञ और यूनिसेफ अधिकारी सौरभ भट्टाचार्य ने स्वस्थ रहने के लिए घर के बने खाने और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाने पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही, अभिनेत्री अनु चौधरी ने अपने खान-पान की आदतों के बारे में जानकारी दी और कम तेल और घर का बना खाना खाने पर अपनी राय रखी। अनंत सिनेमा के नायक सब्यसाची मिश्रा ने सिनेमा के लिए वज़न बढ़ाने के बाद आई समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने ख़ास तौर पर सभी से च्यूइंग गम, शराब और सिगरेट जैसी बुरी आदतों से दूर रहने का आग्रह किया। अभिनेत्री अर्चिता साहू ने खान-पान की अच्छी आदतों पर चर्चा की।

कार्यक्रम में अतिथियों ने सामाजिक व्यवहार परिवर्तन पर एक पोस्टर का विमोचन किया। विभाग ने कहा है कि यह पोस्टर आँगनवाड़ी के माध्यम से गाँवों में जनजागरूकता पैदा करेगा। विभागीय निदेशक मोनिषा बनर्जी ने स्वागत भाषण दिया और अतिरिक्त शासन सचिव श्रीमती स्वयंप्रभा मोहंती ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पेट्रोल पंप से लेकर सोने की दुकानों तक हर जगह धोखाधड़ी व्याप्त है: खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण पात्र

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: बाट-माप में धोखाधड़ी से सावधान रहें। राज्य सरकार की बेईमान व्यापारियों को सख्त चेतावनी। उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ मामला दर्ज किया जाएगा, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने निर्देश दिए हैं।कई जगहों पर गलत और नकली नाप-तोल उपकरणों से विभिन्न सामान बेचे जा रहे हैं। इसलिए, मंत्री ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किसी पर भी दया न करें। उन पर कड़ा जुर्माना लगाएँ। इससे बेईमान व्यापारियों में डर पैदा होगा। मंत्री ने अधिकारियों से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से काम करने का आह्वान किया। मंत्री ने ब्लॉक स्तर पर भी उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। धोखाधड़ी का शिकार होने पर उपभोक्ताओं को शिकायत करने का साहस दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंप, सोने की दुकानों और यहाँ तक कि चिकन की दुकानों में भी नाप-तोल में धोखाधड़ी हो रही है। मंत्री ने कहा है कि धोखाधड़ी पर नियंत्रण की आवश्यकता है। उन्होंने सोने की दुकानों पर जुर्माना बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और मात्रा पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे इस बात के प्रति जागरूक रहें कि उपभोक्ताओं को सही नाप में सामान कैसे मिल सकता है। अगर बेईमान व्यापारी

सोए रहेंगे तो वे सुधरेंगे नहीं। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उसने लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी।

आपूर्ति मंत्री ने राशन कार्डों की ई-केवाईसी को लेकर बड़ी जानकारी दी। खाद्य आपूर्ति विभाग में ई-केवाईसी लागू होने से पता चला कि 5.75 लाख मृतकों के नाम पर राशन कार्ड थे। उनके नाम पर चावल लिया जा रहा था। आयकर देने वाले 1.5 लाख लोगों ने कार्ड वापस कर दिए हैं। वहीं 6 लाख गरीबों को कार्ड मिले हैं। 1.4 लाख लोगों ने आवेदन किया था और कार्ड का इंतजार कर रहे थे। उन्हें राशन कार्ड नहीं मिले। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी अमीर लोगों ने कार्ड लिए हैं, उन्हें काट दिया जाए। इसी तरह कई अमीर लोगों ने अंत्योदय कार्ड भी ले लिया है। उस पर भी कार्रवाई चल रही है। मंत्री ने कहा कि गरीबों को कार्ड कैसे मिले, इस पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

निकाय चुनाव नहीं कराने पर झारखंड के चार आईएएस को हाईकोर्ट का नोटिस

अदालत ने फटकार भी लगाया 14 अक्टूबर को अगली तारीख

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी फटकार लगायी. अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट रूल-393 के तहत मुख्य सचिव अलका तिवारी, वंदना डाडेल, नगर विकास विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया. अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान सभी अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ अब आरोप गठित किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 14 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी अदालत में सशरीर उपस्थित थीं.

अदालत ने पूछा कि चार जनवरी 2024 के आदेश के तहत तीन सप्ताह में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने की बात थी, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अदालत ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. चुनाव कराने में जानबूझ कर देरी की जा रही है. मुख्य सचिव की ओर से 13 जनवरी 2025 को चार माह के भीतर चुनाव कराने लेने संबंधी अंडरटेकिंग दी गयी थी, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए. बार-बार समय लेकर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराया गया. इसके बाद 18 जुलाई तथा दो सितंबर को हुई सुनवाई में भी राज्य सरकार की ओर से केवल समय मांगा जाता रहा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. समय लेकर टालमटोल किया जाता रहा. यह कार्यशैली जानबूझ कर आदेश की अवमानना करने जैसी है.

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उसके कारण भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन अब चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है. ट्रिपल टेस्ट भी कराया जा चुका है. उपस्थित अधिकारियों ने अदालत से क्षमा याचना करते हुए नोटिस जारी न करने आग्रह किया. हालांकि अदालत ने यह दलील खारिज कर दी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. प्रार्थी रौशनी खलखो व रीना कुमारी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. उन्होंने नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

झारखंड में वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुआ है. कई नगर निगम का संचालन बिना चुनाव कराये किया जा रहा है. राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है. अदालत ने याचिका संख्या 1923/2023 व 2290/2023 में चार जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी कि राज्य द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करके, खासकर जब वह अंतिम रूप ले चुका है, कानून के शासन को भी खतरे में डाला गया है. यह अवज्ञा के अलावा और कुछ नहीं है. ये सब पूरी तरह से राज्य कार्यपालिका के कारण है, जो इसके लिए विशेष रूप से दोषी है.

आदित्यपुर की लड़की को राजस्थान में बेचे जाने का मामला पहुंचा पुलिस के पास

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

राचीं, मानव तस्करी को लेकर विगत कुछ समय से सुर्खियों में रहने वाले राज्यों में से झारखंड , ओडिशा इस इलाका सुमार होने चला है । अब मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जो सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के धीराजगंज से है । यहां लापता लड़की सीता लोहार को लोन दिलाने के बहाने राजस्थान ले जाकर बेचने का आरोप दो लोगों पर लगा है।

आरोपियों की पहचान बास्को नगर की पदमा तांती और शांति नगर निवासी राम के रूप में हुई है। लड़की घर लौटने पर अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद वार्ड पार्षद अभिजीत महतो और उनकी मां ने आरोपियों को घर बुलाकर पूछताछ की।

सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मानव तस्करी में संलिप्त महिला और युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। उधर मानव तस्करी को लेकर सरायकेला खरसावां , सिंहभूम ही नहीं तमाम सीमा इलाका समेत ओडिशा के मयूरभंज जिले तक इसकी छींटे पहले से ही जांच का विषय बना हुआ है ।

जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार — उपभोक्ताओं को राहत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी- व्यापार मंडल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची ,चिटफंड कंपनी एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड ने देवघर में कई लोगों को चूना लगाया गया है. इसकी जांच सीबीआइ धनबाद कर रही है. इसी सिलसिले में मंगलवार को सीबीआइ धनबाद की टीम और इस केस के आइओ इंस्पेक्टर सीबीआइ रघुनाथ प्रसाद देवघर सर्किट हाउस में कैंप कर रहे हैं. सीबीआइ की टीम के समक्ष 10 से 12 सितंबर तक इस कंपनी में निवेश करने वाले लोग संबंधित कंपनी से मिले दस्तावेजों के साथ बेझिझक आयें और अपनी बात रखें. ज्ञात हो कि 2013 में देवघर में तत्कालीन एसडीओ ने व्यापक पैमाने पर नन बैंकिंग/चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया था. जिसमें एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड की शाखा भी सील की गयी. उस छापेमारी के दौरान उक्त चीटफंड कंपनी के देवघर कार्यालय से 12.43 करोड़ के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले थे. हाइलाइट्स एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड के निवेशक अपने दस्तावेज लेकर सीबीआइ टीम से मिलें देवघर सर्किट हाउस में 10 से 12 सितंबर तक टीम करेगी कैंप।

अमृतसर के गांधी मैदान में पंजाब राज्य महिला टी-20 टूर्नामेंट , पीसीए ग्रीन ने जीता खिताब

अमृतसर 11 सितंबर (साहिल बेरी)

पीसीए उपाध्यक्ष दीपक बाली ने विजेता टीम को सम्मानित किया, एशिया कप के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं

पहले बल्लेबाजी करते हुए, पीसीए ब्लू ने 20 ओवरों में 74 रन बनाए और जवाब में, पीसीए ग्रीन ने 16 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया। विजेता टीम को 2 लाख रुपये से अधिक की ट्रॉफी और उपविजेता को 1 लाख रुपये से अधिक की ट्रॉफी मिली।

बेटियाँ किसी से कम नहीं, खेल ही दिलाएगा नशे से छुटकारा - अमृतसर खेल संघ सचिव नवजोत ग्रोवर

पंजाब राज्य महिला टी-20 टूर्नामेंट का फाइनल मैच अमृतसर के गांधी मैदान में शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान पीसीए ग्रीन की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। यह पहली बार था जब पंजाब क्रिकेट संघ द्वारा अमृतसर में इस स्तर का महिला टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसने खेल प्रेमियों के दिलों में नया जोश भर दिया।

पंजाब क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष दीपक बाली फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय टीम को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं भी दीं और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट भविष्य के खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर खेलने का मौका देते हैं। पीसीए ग्रीन की कप्तान मन्नत ने खुशी जताते हुए कहा कि टूर्नामेंट काफी कठिन था, लेकिन टीम ने हिम्मत और मेहनत से खेलते हुए जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह खेल न केवल लड़कियों को आत्मविश्वास देता है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जो लोग आज भी लड़कियों को घरों तक ही सीमित रखने की सोच रखते हैं, उनके लिए यह जीत एक स्पष्ट संदेश है कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर हैं। अमृतसर गेम एसोसिएशन की मानद सचिव नवजोत ग्रोवर ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। हम चाहते हैं कि माझा की धरती की लड़कियां आगे बढ़ें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें। इस टूर्नामेंट में पंजाब के विभिन्न जिलों से लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिससे साबित होता है कि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। खेलों को बढ़ावा देकर हम पंजाब को नशे जैसी बुराइयों से बचा सकते हैं। इस मौके पर पीसीए के उपाध्यक्ष दीपक बाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि अमृतसर में पहली बार इस स्तर का महिला टूर्नामेंट आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियां दोनों हमारे लिए बच्चे हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम 50% आबादी यानी लड़कियों को पीछे रखेंगे, तो हम अपनी आधी ताकत खो देंगे। इसलिए, हर क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करना समय की मांग है। टूर्नामेंट में पंजाब के विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों को लेकर बनाई गई चार टीमों ने हिस्सा लिया। 10 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, बल्कि अभिभावकों को यह विश्वास भी दिलाया कि उनकी बेटियाँ भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकती हैं।

अंधविश्वास ने ओझा का जीभ काटा फिर ठंडे से पीट ली जान, दो गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

राचीं , झारखंड के चतरा जिला से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति की ओझा-गुणी की आशंका में दबंगों के द्वारा हत्या कर दी गई. आरोपियों ने पहले धारदार हथियार से उसका जीभ काट डाला. इसके बाद उसकी लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्याकांड को अंजाम देने के उपरांत दबंगों ने उसके शव को जला डाला. मृतक की पहचान धर्मदेव उरांव नाम से हुई है.

मामला जिले के टंडवा थाना क्षेत्र खूंटीटोला गांव का है. यहां हुए हत्याकांड की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस जैसे ही गांव पहुंची वैसे ही सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है. मामले में मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले धर्मदेव उरांव के पड़ोस में ही रहने वाले युवक की मौत हो गई थी. युवक की मौत के बाद उसके परिजन धर्मदेव गुनाहों को ही उसकी मौत के लिए जिम्मेवार बताते थे. वे लोगों उसे बेटे पर ओझा-गुणी करने का आरोप लगाया करते थे।

डीआईजी ने बाढ़ प्रभावित सीमा चौकियों और 117 बटालियन बीएसएफ के फ्लैश फ्लड प्रभावित गहराई क्षेत्र का किया दौरा

अमृतसर 11 सितंबर (साहिल बेरी)

11.09.2025 को दोपहर 12:50 बजे से, श्री जसविंदर कुमार बिर्डी, डीआईजी एसएचक्यू बीएसएफ गुरदासपुर, श्री बृज मोहन पुरोहित, कमांडेंट 117 बटालियन बीएसएफ, श्री आदर्श कुमार सैनी (जेडआईसी-ऑप्स), श्री उमेद सिंह दरियाल (डीसी/एडजट.), तथा श्री अमित कुमार सिंह (एसी/क्यूएम) के साथ बॉर्डर आउट पोस्ट शाहपुर, शाहपुर फॉरवर्ड, चन्ना पट्टन, छानिया और पंजग्रेन पहुंचे। इन स्थानों तक उन्होंने ट्रैक्टर, नाव और पैदल विभिन्न साधनों से यात्रा की।

117 बटालियन बीएसएफ क्षेत्र का गहन निरीक्षण करने के बाद, दौरा करने वाले अधिकारी ने सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत की और स्थल पर हुए नुकसान का जायज़ा लिया। डीआईजी ने हाल ही में आई फ्लैश फ्लड से बुरी तरह प्रभावित गहराई वाले क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य जमीनी हालात की समीक्षा करना, नुकसान का आकलन करना और कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों की सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना था।

दौरे के दौरान डीआईजी ने प्रभावित बीओपी पर तैनात अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और विपरीत मौसम व परिचालन संबंधी चुनौतियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बनाए रखने के उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने ढांचागत सुविधाओं, संचार लाइनों और आवश्यक आपूर्ति को हुए नुकसान का जायज़ा लिया और भरोसा दिलाया कि बहाली के लिए आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जा रहे हैं।

डीआईजी ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए उच्च सतर्कता बनाए रखने पर ज़ोर दिया और क्षेत्रीय कमांडरों को स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि समय पर राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। विशेष ध्यान लॉजिस्टिक सपोर्ट, चिकित्सा सुविधाओं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों की भलाई पर देने के निर्देश दिए गए।

डीआईजी ने प्राकृतिक आपदा के बावजूद राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में उनकी अडिग प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने दोहराया कि सीमा सुरक्षा बल का संकल्प सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय जनता को मानवीय सहायता उपलब्ध कराना भी है।

वधिक डिप्टी कमिश्नर ने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए भेजी गई वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रिलायंस फाउंडेशन ने पशुओं के लिए 400 क्विंटल हरा चारा भी वितरित किया

अमृतसर, (साहिल बेरी)

रावी दरिया से सटे अजनाला के कई गांवों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, यहां तक कि घर, ज़मीन और पशु भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। इन प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई संस्थाएँ ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं और जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

इसी क्रम में आज वधिक डिप्टी कमिश्नर डॉ. अमनदीप कौर ने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ी को, जिसे "नॉलेज ऑन व्हील्स" अभियान का नाम दिया गया है, हरी झंडी दिखाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए रवाना किया।

उन्होंने बताया कि अजनाला और रामदास ब्लॉकों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक जन-स्वास्थ्य प्रचार अभियान शुरू किया गया है। नॉलेज ऑन व्हील्स रामदास पी.एच.सी. के अधीन आने वाले तीन गांव—मेहमेड़, मंदरोंवाला और पंडोरी—तक पहुँचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूक करेगा और डॉक्टरों की टीमें लोगों की स्वास्थ्य जांच भी करेंगी। विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं को इन जागरूकता सत्रों में शामिल किया जाएगा।

वधिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ के बाद कई भयंकर बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। इन्हें रोकने के लिए रिलायंस फाउंडेशन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस अभियान में फाउंडेशन की डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नेशनल एक्सपर्ट टीम रिलायंस जियो के हेड ऑफ बिज़नेस के साथ मिलकर सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रिलायंस फाउंडेशन ने बाढ़ प्रभावित गांव बेदी छन्ना में पशुओं के लिए लगभग 400 क्विंटल हरा चारा वितरित किया है, ताकि आपातकालीन चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023